जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्ष: 47 संख्या: 288 प्रभात बीकानेर, बुधवार 13 मई, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

घाटगेट स्थित एसओजी ऑफिस में नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम पहुंची। एसओजी ने सीकर व जयपुर से लगभग 150 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स व कोचिंग संस्थान के संचालकों से पूछताछ करके 15 स्टूडेंट्स को डिटेन किया है उनको सीबीआई टीम के सुपुर्द किया जाएगा। क्योंकि नीट की परीक्षा रद्द करके सीबीआई को जांच सौंपी गई हैं। एसओजी में पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लाम्बा ने मीडिया को जानकारी दी। आरपीएससी सदस्य शिव सिंह राठौड़ को भी एसओजी ने पूछताछ के बाद जाने दिया। राठौड़ ने जाते समय मीडिया से बातचीत की।

पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 3 मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा कथित पेपरलीक के बाद रद्द कर दी गई है। इस कथित पेपर लीक के कारण लगभग 22 लाख छात्र प्रभावित हुए।

केन्द्र ने यह भी घोषणा की कि देश की सबसे बड़ी अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा पुन: आयोजित की जाएंगी, जिसकी तारीखें बाद में सूचित की जाएगी। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

एक बयान में नेशनल टैस्टिंग एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय केन्द्रीय

- **नैशनल टैस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की कि नए सिरे से परीक्षा के लिए जल्दी ही कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।**

एजेंसियों के समन्वय में प्राप्त जानकारी की समीक्षा के बाद लिया गया, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जांच रिपोर्टों ने परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा को स्वीकार करते हुए, एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री के नाम पर कांग्रेस में अनिश्चितता, भाजपा को भा रही है?

भाजपा को अभी तक भारी प्रयासों के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो पाई थी केरल में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। आठ दिन हो गए हैं, कांग्रेस ने राज्य में भारी बहुमत जीतकर केरल में 10 साल के वाम शासन का अंत किया, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा।

कई दौर की बैठकों के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया। देर रात, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से दिल्ली वापस बुलाया गया, तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व फिर से बैठक में जुट गया।

पार्टी नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल, जिनके पास अधिक संख्या में विधायक हैं, और पार्टी नेता सतीशन, जिनके पास केरल में व्यापक बाहरी समर्थन और कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल का समर्थन है, के बीच फंसा हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी वह बात नहीं समझ रहे है जो सबको पता है कि अगर के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यह कांग्रेस के भीतर विद्रोह को जन्म

- **भाजपा प्रसन्न है कि अगर वेणुगोपाल को मु.मंत्री बनाया गया तो केरल में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ज्यादा दिन अपनी निराशा पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तथा भाजपा को पैर जमाने का मौका मिल जाएगा।**
- **वेणुगोपाल ने पार्टी के संगठन मंत्री होने के कारण, पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट बाँटे थे। अतः प्रथम दृष्टया, विजयी विधायक, आँख की शर्म के कारण वेणुगोपाल के साथ दिखते हैं। पर, विधानसभा में विपक्ष के नेता सतीशन, जमीनी स्तर पर ज्यादा लोकप्रिय हैं तथा उनकी शिकायत है कि जब वेणुगोपाल दिल्ली में ''पावर पोलिटिक्स'' कर रहे थे, तब वे केरल में कार्यकर्ताओं के बीच काम में जुटे थे। ऐसी स्थिति में अगर वेणुगोपाल मु.मंत्री बनाये जाते हैं तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, अपनी निराशा पर ज्यादा दिन नियंत्रण नहीं रख पाएगा और भाजपा को पैर पसारने का आसान रास्ता मिल जाएगा।**

दे सकता है, जिससे राज्य में लंबे समय तक भाजपा को दूर रखने वाला माहौल बदल सकता है।

बताया गया है कि के.सी. वेणुगोपाल ने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा है कि राहुल ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं। वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव से पहले राहुल को राज्य में हो रही गतिविधियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका, पाकिस्तान की ''तटस्थता'' को संदेह की दृष्टि से देख रहा है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। अमेरिका-ईरान संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका वॉशिंगटन में जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प प्रशासन के कुछ वर्गों को शक है कि इस्लामाबाद एक खतरनाक दोहरा खेल खेल रहा है, एक ओर वो सार्वजनिक तौर पर तो कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी ओर पर्दे के पीछे कथित तौर पर तेहरान की मदद कर रहा है।

यह अविश्वास तब और बढ़ गया, जब खबर आई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह संदेश पाकिस्तान के माध्यम से भेजा था, जिसने हाल ही में अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी की थी। सी.एन.एन. की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प के निकट कई अधिकारी मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस्लामााद ने बातचीत में आई रुकावट को लेकर वॉशिंगटन की नाराज़गी को तेहरान तक सही-सही पहुँचाया था।

यह चिंता उस समय और बढ़ गई, जब सी.बी.एस. न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी सैन्य विमानों को रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस का उपयोग करने की अनुमति दे दी।

- **अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान, तेहरान से सहानुभूति रखता है तथा उसने ईरान की सेना के विमानों को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को काम में लेने की छूट भी दी थी, जिससे ईरान के विमानों को अमेरिका की ''एयर स्ट्राइक'' से बचाया जा सके।**

ऐसा करके उसने संभवत: उन विमानों को संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया, जबकि इस्लामाबाद दुनिया के सामने खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था।

दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सी.बी.एस. ने बताया कि ट्रम्प द्वारा अप्रैल की शुरुआत में ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद, तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान भेजे, जिनमें ईरानी वायु सेना का आरसी-130 टोही विमान शामिल था। यह लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस का निगरानी और खुफिया संग्रहण संस्करण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने कुछ नागरिक विमान अफगानिस्तान स्थानांतरित किए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उनमें सैन्य उपकरण शामिल थे या नहीं।

इन आरोपों के कारण अमेरिकी प्रशासन के कुछ हिस्सों में अविश्वास बढ़ गया है। वहाँ के अधिकारियों को अब लगने लगा है कि शायद पाकिस्तान वॉशिंगटन के रूख को तेहरान तक मजबूती से नहीं पहुँचा रहा है, जिससे ईरानी नेतृत्व में बातचीत के भविष्य को लेकर अलग-अलग व्याख्याएँ उभर रही हैं।

यह मतभेद तब खुलकर सामने आया, जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने तेहरान की भविष्य की रणनीति को लेकर चुनौतीपूर्ण रुख अपनाया।

उन्होंने कहा, ''अब हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं, या तो हम सम्मान, अधिकार और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठें और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को प्राप्त करें, या हम ''न युद्ध, न शांति'' की स्थिति में रहें, या हम युद्ध और टकराव के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।

उन्होंने कहा कि ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन केवल सैन्य ताकत और राष्ट्रीय गरिमा की स्थिति के साथ।

उन्होंने आगे कहा, ''तर्कसंगत, तार्किक और राष्ट्रीय हित पर आधारित प्राथमिकता यह है कि जो जीत सशस्त्र बलों ने युद्धक्षेत्र में प्राप्त की, वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पेपर लीक- नासिक का प्रिंटिंग प्रेस संचालक गिरफ्तार

नासिक, 12 मई। मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा 2026 की प्रश्नपत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के

- **प्रश्नपत्र नासिक की प्रेस में छपा, फिर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार व केरल भेजा गया।**

नासिक का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में नासिक स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक की संलिप्तता उजागर हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यह जानकारी नासिक पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त किरण चव्हाण, सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके और परिमंडल दो के पुलिस उपायुक्त किशोर काले ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी।

जांच में सामने आया है कि प्रश्नपत्र नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। इसके बाद इस प्रश्नपत्र के हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, बिहार और केरल जैसे राज्यों तक पहुंचने के संदिग्ध रास्ते भी उजागर हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है तथा और भी लोगों से पूछताछ की संभावना है।

'अगले दो साल भारी कंस्ट्रक्शन व ''डिमोलेशन'' पर प्रतिबंध हो'

नीति आयोग ने पश्चिमी एशिया की स्थिति के कारण, ''बैल्ट टाइट'' करने के ठोस कदम सुझाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। कठोर वित्तीय नियंत्रण की नीति तेजी से लागू होती नजर आ रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों को ईंधन खर्च कम करने, सोना खरीदना बंद करने और ''कोविड जैसी स्थिति'' के लिए तैयार रहने की सलाह दिये जाने के बाद, नीति आयोग, जो केन्द्र सरकार का थिंक टैंक है, ने एक सलाह जारी की है, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को रोकने का सुझाव दिया गया है।

यदि यह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो जिन भवनों के निर्माण/तोड़फोड़ के कार्य चल रहे हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा, जैसे निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन आदि। ये गतिविधियाँ मोदी सरकार की सैन्ट्रल विस्टा को फिर से डिजाइन करने की योजना का हिस्सा हैं।

ऐसा लगता है कि इस सलाह के

- **नीति आयोग की यह हिदायत स्वीकार कर ली गई तो दिल्ली में निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन पर कंस्ट्रक्शन गतिविधि पूर्णतया स्थगित कर दी जाएगी।**
- **पर, इन सार्वजनिक भवनों का पुनर्निर्माण मोदी सरकार की ''सैंट्रल विस्टा'' को पुनः डिज़ायन करने की महत्वाकांक्षी योजना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।**

माध्यम से, नीति आयोग पश्चिम एशिया संकट और तेल आपूर्ति में व्यवधान के कारण आवश्यक कठोर वित्तीय माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। निर्माण/तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए भारी मशीनरी, गैस कटर, क्रशर, क्रेन और बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण, ईंधन की जरूरत होती है। पश्चिम एशिया संकट द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, नीति आयोग ने इन गतिविधियों को दो वर्षों के लिए रोकने की सिफारिश की है।

प्रधानमंत्री की कठोर वित्तीय अपील का विपक्षी नेताओं और आम नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया है, जिन्होंने चुनाव प्रचार और अन्य कार्यक्रमों में सरकार के व्यय के मामलों को उजागर किया है। नेटिज़न्स ने प्रधानमंत्री के उस रोड शो पर भी सवाल उठाए, जो उन्होंने 10 मई को हैदराबाद में नागरिकों को वित्तीय अनुशासन की सलाह देने के तुरंत बाद आयोजित किया। उस अवसर पर लगभग 100 कारों का काफिला प्रधानमंत्री के साथ चला, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता लगभग 50 वाहनों के काफिले के साथ जा रहे थे। प्रधानमंत्री के शुक्रवार से शुरू होने वाले पांच देशों के दौरे को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है।

नीति आयोग की यह सलाह नागरिकों और विपक्षी नेताओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकने का प्रयास भी प्रतीत होती है, क्योंकि यह सार्वजनिक खर्च में भी रोक का सुझाव देती है।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक लाहिड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लाहिड़ी एक अर्थशास्त्री हैं और 2021 से 2026 तक बलूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा के भाजपा सदस्य रहे हैं।

आज हो सकता है केरल के मु.मंत्री का फैसला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। कांग्रेस पार्टी केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा संभवत: मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह कर सकती है।

राहुल गांधी ने 10 जनपथ में केरल के पार्टी नेताओं के साथ बैठकों में कांग्रेस महासचिव के.सी.

- **कांग्रेस पार्टी में 10 जनपथ पर भारी विचार मंथन चल रहा है।**

वेणुगोपाल के समर्थन में अधिक समर्थन पाया। मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य मुकाबला सतीशन और वेणुगोपाल में है, जबकि तीसरे उम्मीदवार रमेश चेनिथला ने खुद को हटा लिया, क्योंकि उन्हें पूर्व राज्य अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों का समर्थन नहीं मिला।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व व्यापक परामर्श ले रहा है, क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने रूस के एलएनजी सप्लाई को अस्वीकार किया

भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका की नाराज़गी का जोखिम नहीं उठाना चाहता

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की नाराज़गी से बचने के स्पष्ट कदम के रूप में, मोदी सरकार ने कथित तौर पर रूस के लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) बेचने के प्रस्ताव को अस्वीकार दिया, जो अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत था, जबकि मध्य पूर्व में तनाव के कारण आपूर्ति में कमी थी।

एक एलएनजी जहाज, जो भारत में आने वाला था, अब फंसा हुआ है क्योंकि नई दिल्ली ने रूस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।

एक उच्च स्तरीय सूत्र ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शीर्ष निर्णय निर्माता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल शामिल हैं, ट्रम्प के गुस्से से डर रहे हैं और देश हित में निर्णय लेने की स्वतंत्रता छोड़ने तक के लिए तैयार हैं।

दो सूत्रों, जिनको इस मामले की प्रत्यक्ष जानकारी है, ने रॉयटर्स को बताया कि भारत के लिए निर्धारित रूस के एक टैंकर को लटका कर रखा गया है, स्वीकृत कार्गो पर बातचीत चल रही है। जबकि मध्य एशिया के तनाव के कारण, ऊर्जा-आपूर्ति जबरदस्त रूप से प्रभावित है।

भारत का रुख इस बात को उजागर करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित एलएनजी कार्गो की खरीद टालने के बीच कितनी सावधानी से संतुलन साध रहा है। इससे

- **जैसा कि विदित ही है, अमेरिका ने रूस से एलएनजी के खरीद पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा रखा है।**
- **इसी कारण से रूस का जहाज जो भारत के लिए एलएनजी लेकर रवाना हुआ था, भारत के बंदरगाह दाहोज पर अपना माल उतारने के लिए, अपना माल नहीं उतार पाया और अब सिंगापुर के आस-पास भटक रहा है।**

यह भी पता चलता है कि मॉस्को की अपने एलएनजी निर्यात को नए बाज़ारों में स्थानांतरित कर सकने की क्षमता सीमित है।

एक सूत्र ने बताया कि भारत की हिचकिचाहट के कारण, रूस के बाल्टिक सागर स्थित यूएस प्रतिबंधित पोर्टोवाया प्लांट से एक एलएनजी कार्गो अनलोड नहीं हो सका, जबकि इसे अप्रैल के मध्य में भारत पहुँचना था। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जहाज को ट्रैक किया गया, जबकि दस्तावेज़ इस बात का संकेत दे रहे थे कि कार्गो गैर-रूसी था।

रॉयटर्स ने अप्रैल के मध्य में एलएसईजी शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए बताया था कि 1,38,200-क्यूबिक-मीटर क्षमता वाला टैंकर कुनपेंग भारत के पश्चिमी हिस्से के दाहेज इम्पोर्ट टर्मिनल की ओर जा रहा था। एलएसईजी के अनुसार, अब यह जहाज सिंगापुर के पास समुद्र में है और इसका कोई गंतव्य नहीं बताया गया है।

एक सूत्र ने बताया, भारत, रूस का सबसे समुद्री क्रूड तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और भारत ने 30 अप्रैल को रूस के उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन को इस निर्णय से अवगत किया कि वह प्रतिबंधित एलएनजी नहीं खरीदेगा। उस दौरान सोरोकिन ने भारतीय अधिकारियों, जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे, से मुलाकात की। यह पिछले कुछ महीनों में उनकी दूसरी बैठक थी, और सोरोकिन जून में पुन: बातचीत के लिए लौट सकते हैं।

भारत के तेल और गैस मंत्रालय और रूस के दिल्ली स्थित दूतावास ने तुरंत टिप्पणी के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

इस बीच, भारत की रूस से क्रूड तेल की खरीद लगातार जारी है, जिसे फरवरी 28 से शुरू हुए अमेरिका-इज़रायल युद्ध के कारण ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिली है।

आर्कटिक एलएनजी 2 रूस का दूसरा निर्यात प्लांट है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। अमेरिका ने 2025 की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के एलएनजी प्लांटों पर प्रतिबंध बढ़ा दिए।

एक सूत्र ने बताया, जहाजों के माध्यम से क्रूड तेल को छुपाया जा सकता है, लेकिन एलएनजी शिपमेंट को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 दुबारा सितंबर को होगी

अजमेर, 12 मई (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पुन: आयोजन 20 सितंबर 2026 (रविवार) को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे।

- **अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी और पत्राचार का पता 16 से 30 मई तक अपडेट कर सकते हैं।**

आयोग के अनुसार, भर्ती से संबंधित आयु सीमा, आरक्षण, शैक्षिणक योग्यता एवं अन्य सभी शर्तें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

आनंद वह ख़ुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पड़ता। –सुकरात

सरकार काम कर रही है यह बताने के लिये ग्राम रथ

सरकारें जब काम करती हैं तो उन्हें अपना काम आम जनता को दिखाना भी होता है ताकि सत्तारूढ़ दल के सदस्य जब फिर वोट मांगने अवाम के बीच जायें तो उन पर यह तोहमत न लगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार के कामों का भयंकर प्रचार भी चुनाव में किसी काम नहीं आया था। हमने राजस्थान में भी विधानसभा के पिछले चुनावों में धुआंधार प्रचार के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर होते देखा है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब सरकार के पूरे कार्यकाल में प्रचार अभियान सतत चलाया जाने लगा है। एक के बाद एक सरकारी ईवेंट किये जाने लगे हैं, जिससे उसके वे काम जनता को दिखें जिसे वह बताना चाहती है। ऐसा ही एक ईवेंट 'ग्राम रथ' का राजस्थान में चल रहा है। सरकारें विकास कार्य करती हैं, योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं, परंतु यह सब तब तक राजनीतिक रूप से सार्थक नहीं होता जब तक वह आम जनता की चेतना में न दिखने लगे। इसके लिये पेशेवर प्रचार विशेषज्ञ नये-नये तरीके ईजाद करते रहते हैं। उनका नया आइडिया यह है कि प्रचार चुनाओं के समय ही नहीं सतत चलता रहना चाहिए ताकि संदेश मतदाताओं के मस्तिष्क में ठीक से बिठाया जा सके। इसके पीछे प्रचार उद्योग का अपना मुनाफा भी है। पहले प्रचार उद्योग मनोरंजन जगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं निर्माताओं अथवा किसी संस्थान या ब्रांड की छवि चमकाने के लिये काम करता था। नई सदी में उनकी मांग राजनीतिक जगत में भी होने लगी है। सत्तारूढ़ राजनैतिक दलों को यह लाभ होता है कि उनका ज्यादातर प्रचार का खर्च सरकार के कामों के प्रचार के नाम पर राजकोष से हो जाता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि सरकारों का प्रचार पर खर्च साल-दर-साल बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में हम राजस्थान सरकार के वर्तमान में चल रहे 'प्रचार रथों' के अभियान को समझ सकते हैं। राजस्थान सरकार के प्रचार का यह केवल साधारण सूचना अभियान नहीं हैं, बल्कि ऐसे अभियान आधुनिक राजनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभर रहे हैं। इन्हें केवल प्रचार का माध्यम मानना एक सीमित दृष्टिकोण होगा। इनके पीछे कई परतों वाली रणनीति कार्य करती है कि शासन लोगों को दिखे, जिसका लाभ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिले। इसलिए इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के पदाधिकारी इन रथों के सारथी बनाये गए हैं।

डिजिटल युग में भी भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां प्रत्यक्ष संपर्क का महत्व बना हुआ है। प्रचार रथ इस प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम बनते हैं। इसीलिए राजस्थान की 200 में से 183 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे रथ चल रहे हैं। ये सभी क्षेत्र ग्रामीण हैं। शेष 17 विधानसभा क्षेत्र शहरी हैं जहां इनकी जरूरत नहीं समझी गई हैं। शायद ऐसा माना गया है कि वहां स्मार्टफोन पर सीधे या इन्फ़्लुएन्सरों के जरिए प्रचार को पहुंचा दिया जाएगा। सरकारी योजनाएं अक्सर जटिल होती हैं और उनकी जानकारी हर नागरिक तक स्वतः नहीं पहुंचती। कई बार लाभार्थी स्वयं यह नहीं जान पाते कि उन्हें जो सुविधा मिल रही है, वह किस योजना के अंतर्गत है। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम रथ इस अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सक्रिय और संवेदनशील है। यह दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जो दिखता है, वही अक्सर सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। प्रत्येक ग्राम रथ एक छोटा वाहन है जिस पर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन लगी है। इसमें ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति है जिसका काम है कि कंप्यूटर में दी गई वीडिओ क्लिप जगह-जगह चला कर लोगों को दिखाना। करीब 15 क्लिप मिलाकर कुल लगभग एक घंटे की हैं। सभी में बताने का प्रयास किया गया है कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम किये हैं। इस अभियान की गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस प्रचार पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन तंत्र के प्रमुख मुख्य सचिव स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूचना और जनसंपर्क विभाग इन रथों का संचालन जिला परिषदों के माध्यम से कर रहा है। रथ के ठहराव के स्थानों पर स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन भी शामिल किये गए हैं। ग्राम रथों से ग्रामीण आबादी कितनी प्रभावित हो रही है इसका पता तो जब चुनाव होंगे उनके परिणाम ही देंगे मगर अभी ऊपर से सारा जोर इस बात पर है कि रथ के कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं उनकी विडियो रिपोर्टें सोशल मीडिया पर निरंतर डाली जाए। सब जगहों से रथों के इवेन्टों के फ़ोटो और विडिओ डलवाने के लिये जयपुर में बैठे प्रशासन के आला अफसर दिन रात नीचे के लोगों को हैरान-परेशान किये हुए हैं। यहां हमें उस मूल द्वंद्व को समझना होगा जो आज की राजनीति में गहराई से मौजूद है-काम (सरकार का प्रदर्शन) बनाम धारणा (परसेप्शन)। यह नये जमाने में लोकतंत्र का बदलता समीकरण है। लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप में यह माना जाता है कि मतदाता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर वोट देता है। लेकिन व्यवहार में स्थिति ऐसी होती नहीं है। मतदाता का निर्णय केवल ठोस उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक धारणाओं से भी उसका मन प्रभावित होता है जिसके आधार पर वह वोट देता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र से पड़ने वाले रास्ते से भी उसकी सरकार के प्रति धारणा बनती है। लोग अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर वोट देते हैं। यह धारणा कई कारकों से बनती है जैसे मीडिया, सामाजिक संवाद, व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक प्रचार। प्रचार रथ इस धारणा को नियंत्रित और दिशा देने का प्रयास करते हैं। वे एक कथा गढ़ते हैं कि सरकार विकासोन्मुख है, जनहितैषी है और लगातार काम कर रही है। यह कथा बार-बार दोहराई जाती है ताकि वह मतदाता के मन में स्थायी रूप से बैठ जाए। इसके साथ ही अब केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें भावनाओं की अपनी राजनीतिक पूंजी में अपने काम को भी बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है ताकि संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे शासन में भी उसकी वह पैठ भी बने जो उसके भावनात्मक नेरटिव के हिसाब से हो तथा मतदाता का चुनावी व्यवहार उसके पक्ष में प्रभावित हो। सरकार के विकास के कामों के प्रचार से सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास तो करती ही है, साथ ही वह विपक्ष के नैरेटिव का प्रत्युत्तर भी परोक्ष रूप से देती है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। यदि विपक्ष यह धारणा बनाने में सफल हो जाता है कि सरकार निष्क्रिय है या विफल है, तो यह सत्तारूढ़ दल के लिए खतरा बन सकता है। प्रचार के ये रथ इस चुनौती का जवाब हैं। वे एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत करते हैं। मगर सरकारी कोष और मशीनरी के जरिए चलाए जा रहे रथ अभियान पर यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि क्या यह लोकतांत्रिक आवश्यकता है या राजनीतिक प्रचार? यह प्रश्न इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। एक दृष्टिकोण से देखें तो जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलनी आवश्यक है। सरकार को अपने कार्यों का लेखा-जोखा देना चाहिए। संचार के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इस दृष्टि से शासन में बैठे लोगों को प्रचार रथ एक लोकतांत्रिक आवश्यकता प्रतीत होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब सरकारी संसाधनों का उपयोग सत्तारूढ़ दल की छवि सुधारने के लिए होता है, तो यह राजनीतिक प्रचार बन जाता है। इसमें उपलब्धियों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और कमियों को छिपाया जाता है।

> **लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप में यह माना जाता है कि मतदाता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर वोट देता है। लेकिन व्यवहार में स्थिति ऐसी होती नहीं है। मतदाता का निर्णय केवल ठोस उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक धारणाओं से भी उसका मन प्रभावित होता है जिसके आधार पर वह वोट देता है।**

ऐसे में निजी क्षेत्र में फल-फूल रहे प्रचार व्यवसाय को सरकार के इमेज मैनेजमेंट काम भरपूर मिल रहा है। प्रचार के रथ लोकतंत्र और राजनीति के बीच की उस धुंधली रेखा पर चलते हैं जहां जन-सूचना और राजनीतिक स्वार्थ एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। आज की राजनीति में सफलता का समीकरण बदल चुका है। अब केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, और धारणा बनाना भी जरूरी है। इसके लिये प्रभावी संचार आवश्यक हो गया है। राजनीतिक दलों ने यह समझ लिया है कि काम आधार है, धारणा प्रभाव है और संचार पुल है जो दोनों को जोड़ता है। ग्राम रथ इसी पुल का निर्माण करने मे लगे हैं। वे उस जटिल वास्तविकता का हिस्सा हैं जहां सरकारें काम भी करती हैं और उसे दिखाने की आवश्यकता भी महसूस करती हैं। इसके लिये वे राजकोष का इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करतीं। आज का मतदाता जागरूक भी है, लेकिन सोशल मीडिया के जाल में फंसा मतदाता धारणा से अधोक प्रभावित होता है। इन्हीं परिस्थितियों में राजनीति सेवा और रणनीति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है और राजनेता अपने को जनता से सम्बद्ध रखने का प्रयास करते हैं। अंततः, लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि मतदाता कितनी सजगता से इन प्रचार माध्यमों को परखता है। यदि नागरिक केवल दिखावे से प्रभावित होंगे, तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन यदि वे वास्तविक काम और ठोस परिणामों को प्राथमिकता देंगे, तो प्रचार की सीमाएं स्वतः तय हो जाएंगी। इसलिए, असली प्रश्न यह है कि हम, मतदाता, उस प्रचार को कितनी समझदारी से ग्रहण करते हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक)

लोकतंत्र और पार्टी हाईकमान : निर्णय और निर्णायक

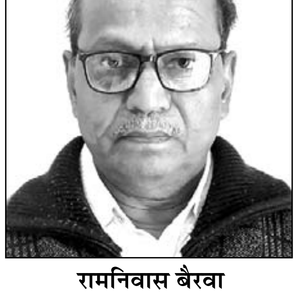

रामनिवास बैरवा

राजनीतिक पार्टियों के निर्णय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी ही अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं ढाल सकती, तब देश का लोकतान्त्रिक आधार तो डांवाडोल होता ही है; उसकी भागीदार राजनीतिक पार्टियां भी, क्रमशः समाप्त होने को बाध्य होती हैं।

भारतीय जनता पार्टी का 'कांग्रेस मुक्त भारत' जैसा नारा या अभियान उसी ही बाध्यता का एक रूप है, जिसमें लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को तिलांजलि देकर 'हाई कमान' के चारों और अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके राजनीति में सफल होने का खेल कर रहे होते हैं। यही 'हाई कमान' की निर्णायक भूमिका की परम्परा ही भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखायेगी।

जब ऐसी पार्टियों का आधार लोकतंत्र नहीं होकर 'पार्टी हाई कमान' ही निर्णायक बन जाते हैं तो सिद्धांतहीनता के अभाव में वे दूसरों पर लांछन लगाते हैं, आपस मे एक दूसरे का चरित्रहनन करते हैं। और फिर इस प्रकार से सभी पार्टियां गलीच बनकर रह जाती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी उसी गलीच चरित्रहनन के स्तर पर ले आती हैं, तब सब एक जैसे हो जाते है।

लेकिन जनता उन पार्टियों के द्वारा आपसी चरित्रहनन के साथ-साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी आदि को भी समय-समय पर अपना नारा बनाये रखने को बाध्य करती हैं। चूंकि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी पूंजीवादी लोकतन्त्र के ऐसे आवश्यक विषय हैं, जिनको बनाये रखना उनके लिए आवश्यक है। उनको खतम करना उन कथित राजनीतिक पार्टियों के लिए घातक होता है, अतः कुछ और नया जोड़ने की कोशिश की जाती रही है।

जहां कांग्रेस गांधीजी को और स्वतंत्रता प्राप्ति को अपनी परम उपलब्धी होने का बखान करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रूढ़ियों को सनातन सत्य बताकर अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाये रखने का प्रयासरत रही है। लेकिन जिस संविधान आढ़ में राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्त करती हैं, उसी संविधान को अपनी-अपनी सत्ता के स्थायित्व में अवरोध भी मानती हैं। अतः वे संविधान की व्याख्या अपने-अपने स्वार्थों के अनुसार करती हैं और नौकरशाहों का उपयोग करती है, विचारधारा को छोड़ देती हैं। इस प्रकार से लोगों की विचार भिन्नता को दवाये रखने के लिए एक ही व्यक्ति के आदेशों के अनुसार चलने की परम्परा डाली जाती है। पार्टी हाई कमान बनने का सबसे पहला प्रयोग 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। उस समय, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों के द्वारा कांग्रेस के मंच पर मोहम्मद अली जिन्ना को बेइज्जत करके मंच से ही नहीं कांग्रेस से भी हट जाने को मजबूर किया था तथा 'महात्मा' बनने के चक्कर में गांधीजी ने वह सब बाखुशी देखा और मौन रहकर कांग्रेस पार्टी की अलोकतान्त्रिक कार्य प्रणाली के 'हाई कमान' बने।

उसके बाद, जब तक गांधीजी जिंदा रहे, कांग्रेस के हाई कमान बने रहे और मरने के बाद राष्ट्रपिता बना दिये गये। लेकिन, 1920 में चरित्रहनन करने वालों को आगे की सम्भावनाएं कम दिखी, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संस्था बनाकर आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 'कांग्रेस विहीन भारत' का नारा देकर, उसी 'हाई कमान' वाली व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक पार्टी के सहारे, बेशक सत्ता भोग कर रही हो, लेकिन 'हाई कमान' के निर्णय लोकतन्त्र को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं।

संविधान का आध्याय-चार, 'राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांत' संविधान की आत्मा हैं और उनके लिए काम करना सभी सरकारों, सभी राजनीति पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। उनके लिए काम नहीं करना गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को निरन्तर बनाये रखना है, जिसका विपरीत परिणाम भ्रष्टाचार को अनिवार्यतः फलने-फूलने की परिस्थितियां निरन्तर बनाये रखना है। इस प्रकार उनके लिए, संविधान का अध्याय-चार, उनकी अपनी 'हाई कमान' प्रणाली के लिए कैसे रूकावट बना हुआ है, इसका एक ही उदाहरण देना काफी है।

गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को, जो कि उनका 'मूल-अधिकार' है, को आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए, भारत की समाज व्यवस्था में अछूत-पिछड़ी जातियों को उक्त अध्याय में, संदर्भ देकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था लोगों के आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ ही जाति व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था के अनावश्यक बन जाने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु, वही आरक्षण अब चुनावी लोकतन्त्र की आवश्यकता के साथ-साथ 'हाई कमान' की प्रणाली के लिए भी अनिवार्य बन गया है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण देने के संविधान के प्रावधान को अपना 'ट्रेडमार्क' मानती है, वहीं दूसरी अन्य पार्टियां विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण को अपनी "हाई कमानका मास्टर स्ट्रोक" बनाने की कोशिशों में लगी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन व्यवस्था बनाये रखने को अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क बना चुकी है, उस पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण को सनातनी व्यवस्था यानि कि वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था को समाज व्यवस्था का आवश्यक अंग अनाये रखने की आड़ में आरक्षण को खतम करने का स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का दाव खेल चुकी है। परंतु 2026 में अभी हुए 5 विधान सभाओं के आम चुनावों में किसी भी पार्टी ने, यहां तक कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को उक्त 33 प्रतिशत की मात्रा में चुनावों में टिकिट नहीं दिए।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किसी भी राजनीतिक पार्टी का हाई कमान करना चाहता है। क्योंकि कथित महिला आरक्षण पुरूष सत्ता को और मजबूती देने कि ही प्रचारित किया गया है। आंकड़ों को देखें तो-

अभी संसद में 80-85 महिला सांसद है, जो कि 543 सांसदों का 15.65 प्रतिशत है। जाहिर है कोई भी राजनीति पार्टी, महिला आरक्षण के द्वारा नारी मुक्ति को जोर-शोर से प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी, संसद में 15 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही हैं। लेकिन महिला आरक्षण के नाटक के पीछे इन 15.65 प्रतिशत महिलाओं की सीटें भी अपने पुरूष उम्मीदवारों को देने की कोशिश में संविधान को ही अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए ढ़ाल बना चुकी हैं। क्योंकि महिलाओं को नईबढ़ाई जाने वाली 33 प्रतिशत सीटों में समेटा जायेगा और वर्तमान 15.65 प्रतिशत सीटें अपने पुरूष उम्मीदवारों को दे देंगी।

इसके अलावा एक और षड्यंत्र है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का। और वह यह है कि वर्तमान में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने से उनकी नये-पुराने पुरूष उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी से हाथ धोना पड़ रहा हैं जो कि अपनी-अपनी पार्टियों में विद्रोह, पार्टियों के टूटने के साथ ही नई बनाकर नया हाई कमान का उभारना है जिससे जातियों पर उनकी पकड़ में फूट पड़ती है। इसीलिए 33 प्रतिशत संसद में सीटें बढ़ाकर "महिलाओं को आरक्षण" और उन्हें उसी सीमा में बांधकर रखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित संख्या तक ही सीमित रखा जा रहा है।

फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ रूख किया जाये।

राजीव गांधी की मौत के बाद, 1991 से कांग्रेस में कोई हाई कमान नहीं रही थी। तब तब के चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने कांग्रेस की फूट के बीच गांधी परिवार को फिर से हाई कमान की भूमिका में लाने के प्रयास में कथित चुनाव सुधार लागू किये, जिससे, अंततः सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हुआ और वह आज भी कांग्रेस की हाई कमान बनी हुई है। बेशक, राहुल गांधी को दूसरा हाई कमान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन वह गांधी के सामने का जवाहर लाल नहीं है जो गांधी जी के बाद नया हाई कमान खड़ा कर सके। और यह राहुल गांधी की मानसिक सोच में नहीं है कि वह हाई कमान जैसे सर्व-सुविधाओं से संपन्न हैसियत को छोड़ दे। नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि कांग्रेस में राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत कम हो। क्यों कि वह राहुल गांधी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जुट रख पा रहे हैं, अन्यथा जब कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होगा तो किससे लड़ा जायेगा। इसलिए, एक हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण से ीेंई लेना-देना है और ना ही किसी प्रकार के महिला आरक्षण से कोई लेना-देना है, बस उनकी हाई-कमान की हैसियत बनी रहे, यही उनके लिए लोकतंत्र है और यही उनका लिखा या बिना लिखा संविधान है।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पोखरण परमाणु परीक्षण : 51 वर्ष बाद भी शौर्य, समस्याएं और विकास की अधूरी कहानी बयां करता परीक्षण स्थल

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं

जुगल किशोर बिस्सा

पोकरण भारत की सामरिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा का गौरवशाली प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित इस छोटे से कस्बे ने वर्ष 1974 और 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के कारण पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन राष्ट्रीय गौरव के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों को अनेक समस्याओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पांच परमाणु परीक्षण कर भारत को विश्व की परमाणु शक्तियों में शामिल कर दिया।

इन परीक्षणों के बाद पोकरण का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। देशभर में इसे राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा गया। वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सहित भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को सराहा गया। वर्ष 1998 के परीक्षणों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई।

ग्रामीणों की समस्याएं और प्रभाव : परमाणु परीक्षण स्थल के सबसे निकट बसे खेतोलाई गांव के लोगों का कहना है कि परीक्षणों के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं। ग्रामीणों ने कैंसर, त्वचा रोग, आंखों में जलन, पशुधन पर प्रभाव तथा जन्मजात बीमारियों जैसी शिकायतें उठाई हैं। हालांकि इन दावों पर सरकार की ओर से कोई व्यापक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि परीक्षणों के समय धरती हिल गई थी और कई घरों में दरारें तक आ गई थीं। कई परिवारों का आरोप है कि वर्षों से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन कोई स्थायी मेडिकल रिसर्च या विशेष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बावजूद आज भी पोकरण और आसपास के गांवों में कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। खेतोलाई सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार का अभाव और खराब आधारभूत ढांचे की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि गांवों में पानी की सप्लाई कई-कई दिनों बाद होती है तथा ग्रामीणों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त रूप से संचालित नहीं हो पाते तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं :- परमाणु परीक्षणों के बाद केंद्र सरकार तथा रक्षा संस्थानों द्वारा कुछ विकास कार्य जरूर किए गए। क्षेत्र में सेना और रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से सड़क और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई तथा परीक्षण क्षेत्र को संरक्षित रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर पोकरण को देश की वैज्ञानिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े सीमित रोजगार अवसर भी क्षेत्र में बने। हालांकि स्थानीय लोग लंबे समय से विशेष पैकेज, कैंसर अस्पताल, बेहतर पेयजल योजना, पर्यटन विकास, शिक्षा संस्थान और युवाओं के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं।

मई महीने में ही परीक्षण क्यों किए गए? :- भारत सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण मई महीने में अलग-अलग समय पर किए जाने के पीछे कई सामरिक, वैज्ञानिक और मौसम संबंधी कारण माने जाते हैं। विशेषज्ञों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा था।

रेगिस्तानी मौसम और साफ वातावरण :- पोकरण थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। मई महीने में यहां अत्यधिक गर्मी रहती है और आसमान सामान्यतः साफ रहता है। वैज्ञानिकों के लिए भूमिगत परीक्षण, उपकरणों की निगरानी और सैन्य गतिविधियों को संचालित करना आसान माना गया। गर्म हवाओं और धूल भरे वातावरण के कारण विदेशी उपग्रहों की निगरानी से भी कुछ हद तक बचाव संभव माना जाता था।

विदेशी जासूसी उपग्रहों से बचाव : 1998 के परीक्षण अत्यंत गोपनीय तरीके से किए गए थे। उस समय अमेरिका सहित कई देशों के जासूसी उपग्रह भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिकों और सेना ने रात के समय काम किया तथा गर्म मौसम और रेतीले इलाके का फायदा उठाकर तैयारियां छिपाई। माना जाता है कि मई की तेज गर्मी और धरती की ऊष्मा के कारण उपग्रहों को स्पष्ट गतिविधियां पकड़ने में कठिनाई हुई।

रणनीतिक और राजनीतिक समय :- 1974 के परीक्षण के समय भारत वैश्विक दबाव के बावजूद अपनी परमाणु क्षमता दिखाना चाहता था। वहीं 1998 में भारत ने खुद को खुलकर परमाणु शक्ति घोषित करने का निर्णय लिया। उस समय क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर चीन और पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां, एक बड़ा कारण थीं।

भूमिगत परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थिति :- वैज्ञानिकों के अनुसार मई में जमीन की सूखी और कठोर स्थिति भूमिगत परीक्षणों के लिए उपयुक्त मानी गई। इससे विस्फोट को नियंत्रित रखने और रेडियोधर्मी प्रभाव को सीमित करने में मदद मिली।

11 मई का विशेष महत्व :- 11 मई 1998 को हुए पोखरण-परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।

क्या कोई धार्मिक या ज्योतिषीय कारण था? :- कुछ लोगों द्वारा समय-समय पर धार्मिक या ज्योतिषीय कारणों की चर्चा की जाती रही है, लेकिन सरकार या वैज्ञानिकों ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार परीक्षणों का समय मुख्य रूप से सुरक्षा, गोपनीयता, मौसम और सामरिक रणनीति को ध्यान में रखकर तय किया गया था।

आज भी कायम है गौरव और उपेक्षा का द्वंद्व :- पोकरण आज भी भारत की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहां हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस भूमि ने देश को परमाणु शक्ति बनाया, उसी क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें पोकरण को परमाणु नगरी के रूप में विशेष दर्जा देकर यहां आधुनिक अस्पताल, कैंसर उपचार केंद्र, उच्च शिक्षा संस्थान, पर्यटन विकास, पेयजल परियोजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध करवाएं, ताकि राष्ट्रीय गौरव के साथ स्थानीय जनता का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके।

–जुगल किशोर बिस्सा,
वरिष्ठ पत्रकार।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 13 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 1:30 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 8:35 तक, बालव करण दिन 1:30 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-मेष, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 1:30 से रात्रि 12:18 तक है। आज अपरा एकादशी, भद्रकाली एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी (उड़ीसा), पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:04 तक, शुभ 10:43 से 12:23 तक, चर 3:42 से 5:22 तक, लाभ 5:22 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:02

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना पड़ सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कर्क
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

आरजीएचएस योजना पर कुठाराघात के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आरजीएचएस योजना को तहस नहस करने के सरकार के इरादों के खिलाफ प्रांतीय आव्हान पर मंगलवार 12 मई को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन किया।

महासंघ के जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा व जिला महामंत्री मनोज सुथार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि राज्य के कर्मचारी आरजीएचएस के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। महासंघ नेताओं ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के चिकित्सा अधिकारों के लिए वरदान रूपी आरजीएचएस योजना पर शासन एवं सरकार द्वारा निरंतर हमले किए जा रहे हैं।

कुछ भ्रष्ट निजी चिकित्सा संस्थानों के द्वारा की जा रही सरकारी धन की लूट पर अंकुश लगाने में विफल चिकित्सा विभाग कर्मचारियों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं में कटौती करने एवं इस योजना को इंश्योरेंस मोड पर देने को आमादा है। पिछले एक माह से हजारों कर्मचारी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हो रहे हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को मजबूरन नकद भुगतान कर इलाज करवाना पड़ा है। जिससे लगभग 200 करोड़ रूपए उनकी जेब से खर्च हो चुके हैं।

कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आरजीएचएस योजना पर कुठाराघात के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका।

- **पिछले एक माह से हजारों कर्मचारी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने से गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को मजबूरन नकद भुगतान कर इलाज करवाना पड़ा है**
- **कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया राज्यव्यापी आन्दोलन का ऐलान**

इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त योजना की सुरक्षा तथा संवेदनहीन सरकार की निद्रा खोलने के लिए महासंघ के द्वारा प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी हित एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण में 12 मई को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन किया जायेगा। इसी क्रम में 15 से 25 मई तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्येक राजकीय दौरे के दौरान महासंघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। 28 मई को राजधानी जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया राज्यव्यापी आन्दोलन का ऐलान किया है। प्रदर्शन में संजय पुरोहित, आनंद पारीक, हेतराम, भंवरलाल व्यास, यतीश वर्मा, रामचन्द्र, सुशीला बिश्नोई, बलवीर भादू, महेन्द्र सिंह पंवार, भंवर सांगवा, प्रहलाद राम, मनीष ठाकुर, गोपाल पारीक, युसूफ, अमित स्वामी, संदीप कुमार, राजेश टोक्स , दीपसिंह, हुकमाराम, राजकुमार सिंह जायस, जयपाल कूकणा, रविन्द्र बिश्नोई, बजरंग बिश्नोई, अंजलि व्यास, मोनिका आदि कर्मचारी नेता शामिल हुए।

14 मेडिकल स्टोर्स के लाईसेंस निलंबित

बीकानेर, (कासं)। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाये जाने पर 14 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए गए है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि नापासर स्थित अशोक मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 18 से 21 मई तक, सींथल स्थित स्वामी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, हल्दीराम प्याऊ के पास सागर रोड स्थित श्री बालाजी हेल्थ केयर के अनुज्ञा पत्र 21 से 24 मई तक, जालवाली स्थित जे.डी. मेडिकल स्टोर, जयपुर रोड भारत पेट्रोल पंप के सामने स्थित फार्मा प्वाइंट के अनुज्ञापत्र 25 से 28 मई तक 4 दिनों के लिए, नापासर स्थित अन्नू मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 18 से 22 मई तक 5 दिनों के लिए, खाजूवाला स्थित सी. आर. मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 18 से 24 मई तक 7 दिनों के लिए, सादुल कॉलोनी अम्बेडकर सर्किल के पास स्थित छाबड़ा मेडिकोज का अनुज्ञा पत्र 18 से 27 मई तक, उदासर स्थित श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, नत्थूसर गेट स्थित श्री मालसी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञा पत्र 21 से 30 मई तक, गंगाशहर स्थित विनायक मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 25 मई से 6 जून तक तक के लिए निलंबित किया।

सार-समाचार

12 जुलाई को होगी प्री-पी.जी. परीक्षा

वेटरनरी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषद की बैठक को कुलगुरू डॉ. सुमंत व्यास ने संबोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर की स्नातकोत्तर परिषद की बैठक मंगलवार को कुलगुरू राजुवास, बीकानेर डॉ. सुमंत व्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यशीलता छात्र हित के लिए सर्वोपरि है एवं पाठ्यक्रम की समयावधि में पूर्णता विश्वविद्यालय का प्रमुख दायित्व है। कुलगुरू डॉ. व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण द्वारा कौशल केन्द्रीकरण हेतु अग्रसित है। अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने विभिन्न एजेंडों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष पी.जी. एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 12 जुलाई, 2026 को प्री-पी.जी. परीक्षा (2025-26) आयोजित करवायी जायेगी। परिषद् के सदस्य पूर्व निदेशक, क्लीनिक, राजुवास, बीकानेर प्रो. टी.के. गहलोत ने पी.पी.टी. द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने हेतु सुझाव दिए। परिषद के सदस्य प्रो. बी.के. माथुर (सेवानिवृत प्रधान वैज्ञानिक, काजरी, जोधपुर) ने स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु सुझाव दिए। बैठक के दौरान अधिष्ठाता वेटरनरी महाविद्यालय, बीकानेर प्रो. बी.एन. श्रृंगी, अधिष्ठाता वेटरनरी महाविद्यालय, उदयपुर प्रो. एस.के. शर्म, अधिष्ठाता डेयरी महाविद्यालय, बीकानेर प्रो. राहुल सिंह पाल, निदेशक क्लीनिक प्रो. प्रवीण बिश्नोई, परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुनीता पारीक, परिषद के सदस्य डॉ. राजेश नेहरा, डॉ. दिनेश जैन, डॉ. अशोक कुमार एवं डॉ. जे.पी. कच्छावा उपस्थित थे।

संगठन मजबूत करने का आव्हान

भाजपा बीकानेर देहात जिला संगठनात्मक बैठक को डॉ. मिथिलेश गौतम ने संबोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर देहात की जिला संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों एवं बूथ स्तर तक पार्टी गतिविधियों को प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को आमजन के बीच जाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचानी चाहिए। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आव्हान किया। जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और अनुशासन से लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने के लिए पूरी निष्ठा एवं ऊर्जा के साथ कार्य करें। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सभी से मिलकर कार्य करने का आव्हान किया। जिला मीडिया संयोजक मनीष सोनी ने बताया आज बैठक में प्रदेश प्रवक्ता भवानी पाईवाल, जिला महामंत्री दिलीप सिंह राजपुरोहित, तोलाराम कूंकणा, कैलाश बिश्नोई, जिला उपाध्यक्ष राजपाल सिंह, हेमनाथ जाखड़, जिला मंत्री मनमोहन सिंह सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

बालाजी से दूध से किया अभिषेक

बीकानेर, (कासं)। प्राचीन श्री केसरिया हनुमान मंदिर में चल रहे 82वें स्थापना महोत्सव के अंतर्गत आज विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ श्री हनुमान जी महाराज का 21 औषधियों से पवित्र स्नान करवाया गया, जिसके बाद 5 किलो गाय के दूध से अभिषेक किया गया। इस दिव्य अनुष्ठान को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उपस्थित रहे। पूरे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सम्पन्न हुए। अभिषेक के पश्चात पंचामृत से बाबा का विशेष भोग लगाया गया तथा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ श्री केसरिया हनुमान जी का गुणगान किया। आज के आयोजन में महिलाओं, पुरूषों एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने बाबा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता एवं मंगल जीवन की कामना की। मंदिर के धार्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने में विद्वान पंडितों की विशेष भूमिका रही। सुरेश पुरोहित, अश्विनी जोशी, गौरीशंकर चूरा, विश्वनाथ पुरोहित एवं मनोज आचार्य द्वारा सभी धार्मिक अनुष्ठान से सम्पन्न करवाए गए।

मरम्मत का काम पूरा होने के बाद 45 दिन की नहरबंदी खत्म, पानी छोड़ा

बीकानेर, (कासं)। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद आखिरकार 45 दिन की नहरबंदी समाप्त हो गई है। मरम्मत के काम में कुछ घंटे ज्यादा लगने के कारण सोमवार को पंजाब से करीब 12 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

रात तक पानी की मात्रा बढ़ाकर 500 क्यूसेक कर दी गई। यह पानी करीब 6 दिन का सफर तय करके 17 से 18 मई के बीच बीकानेर पहुंचेगा। इससे पिछले एक महीने से रिजर्व स्टॉक (भंडारित पानी) के भरोसे चल रही शहर और गांवों की पेयजल व्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी।

27 मार्च से नहरबंदी शुरू हुई थी। ये आंशिक नहरबंदी थी और 12 अप्रैल तक 2000 क्यूसेक पानी पीने के लिए मिलता रहा लेकिन 12 अप्रैल से पूर्ण नहरबंदी शुरू हो गई। जिसमें पीने का पानी भी बंद हो गया। बीते 30 दिनों से इंदिरा गांधी नहर पर आश्रित शहर और गांव भंडार किए गए पानी से ही प्यास बुझा रहे हैं। बीती रात 12 बजे हरिके से पानी छोड़ा जाना चाहिए था मगर

- **सोमवार को पंजाब से दोपहर 12 बजे 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया**
- **यह पानी करीब 6 दिन का सफर तय करके 17 से 18 मई के बीच बीकानेर पहुंचेगा**

नहर में फिनिशिंग काम अधूरा होने के कारण करीब 12 घंटे बाद सोमवार की दोपहर 12 बजे 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

पंजाब से छोड़ा गया पानी करीब 50 से 60 घंटे का सफर तय कर 204 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा मसीतावाली हैड पहुंचेगा। वहां से बीकानेर जिला सीमा (सतासर) की दूरी करीब 150 से 170 किलोमीटर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर के बिरधवाल हैड (आरडी 620) से बीछवाल जलाशय के लिए पानी लिया जायेगा, जिसकी दूरी करीब 160 किलोमीटर है। यह नहर ऊंचाई पर होने के कारण यहां पानी पंप करके आगे बढ़ाया जाता है। नहर में एक महीने से जमा कचरे के कारण पानी पहुंचने में करीब 6 दिन का समय लगेगा।

बीछवाल जलाशय में सुबह तक 310 एमएलडी पानी का स्टॉक था। रोजाना 40 एमएलडी की खपत के हिसाब से यहां सिर्फ 7 दिन का पानी बचा है। यदि 17-18 मई तक पानी नहीं पहुंचता है, तो बीछवाल इलाके में पानी की कटौती बढ़ानी पड़ सकती है। इसके लिए कंवरसेन लिफ्ट के पंपिंग स्टेशनों को दुरूस्त रखना होगा। दूसरी ओर गजनेर लिफ्ट से जुड़ने वाले शोभासर जलाशय में 370 एमएलडी पानी है, जो 40 एमएलडी की दैनिक खपत के अनुसार 9 दिन तक चलेगा।

पंजाब सीमा में 116 किलोमीटर क्षेत्र में नहर की मरम्मत का जो काम 3 साल में पूरा होना था। उसे पूरा होने में 6 साल का वक्त लगा। अब तक पंजाब सरकार नहर को जर्जर बताकर राजस्थान को 11 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं दे रही थी।

खनन माफिया का पटवारी पर हमला

नोखा, (कासं)। नोखा उपखंड के पांचू क्षेत्र में हल्का पटवारी अनोपाराम नाई पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। पटवारी उन्हें खनन करने से रोकने गए थे। घटना के विरोध में मंगलवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सभी राजस्व कर्मचारी उपखंड कार्यालय पहुंचे।

उन्होंने एसडीएम गोपाल जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर मामले में शामिल तीनों आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और राजस्व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पटवार संघ के सदस्य भगवंत लोहार ने बताया कि यदि प्रशासन 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो सभी राजस्व कर्मचारी कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद पटवारियों और गिरदावरों ने नायब तहसीलदार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी दी। नोखा क्षेत्र में पटवारी के साथ मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में कार्रवाई न होने पर राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निमिवाल ने भी एक वीडियो जारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

गर्मी की छुट्टियों में करना होगा क्रिएटिव होमवर्क

बीकानेर, (कासं)। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर ने गर्मियों की छुट्टियों में स्कूली बच्चों के होमवर्क को क्रिएटिव बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले के सभी विद्यालयों में सीखे हर दिन स्कूल से घर तक अभियान चलाया जायेगा।

आदेश में कहा गया है कि अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को ऐसा होमवर्क दिया जाए, जिसमें उन्हें स्टोरी लिखनी होगी या फिर अपनी हैंडराइटिंग सुधारने पर काम करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 120 पेज की नई कॉपी अनिवार्य है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की कॉपी को औसतन 6 विषयों में विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक विषय के लिए 12 से 20 पेज का गुणवत्तापूर्ण गृहकार्य। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए थ्री-इन-वन कॉपी का उपयोग।

आदेश के अनुसार गृहकार्य केवल किताबी प्रश्नों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें हैंडराइटिंग सुधारने, चित्रकारी, कविता और कहानी लेखन, भाषा ज्ञान, खोज आधारित लेख, समसामयिक विषयों पर लेखन, महापुरूषों की जीवनी तथा स्थानीय कला-संस्कृति से जुड़ी

- **स्कूली बच्चों को स्टोरी लिखनी होगी, अपनी हैंडराइटिंग सुधारने पर करना होगा काम**

गतिविधियां शामिल की जायेगी। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि अवकाश से पहले विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। विद्यार्थी पढ़ी गई पुस्तकों का सारांश अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। साथ ही परिवार के बुजुर्गों के साथ संवाद, लोक कथाएं और पारिवारिक इतिहास को लिखित रूप में संकलित करने के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।

निर्देशों के अनुसार गृहकार्य 14-15 मई को अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को दिया जायेगा। विद्यालय प्रधानों को इसके क्रियान्वयन और अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवकाश के बाद होमवर्क की जांच कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा।

तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

बीकानेर, (कासं)। शहर के भुट्टों के बास इलाके में पुलिस और बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्कर मेहंदी हसन उर्फ महेन्द्र के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।

कार्रवाई एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई। मौके पर सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र पचार पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार महेन्द्र रत्नू और बीडीए अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार मेहंदी हसन उर्फ महेंद्र के खिलाफ कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। भुट्टों के बास इलाके में हुई इस कार्रवाई

- **मेहंदी हसन के खिलाफ कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं**

के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली। कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बीकानेर पुलिस ने कई हिस्ट्रीशीटरों और तस्करों के खिलाफ अवैध कब्जों, गैरकानूनी कारोबार और आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई तेज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

अरूण चतुर्वेदी तीन दिवसीय बीकानेर यात्रा पर

बीकानेर, (कासं)। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी मंगलवार दोपहर तीन दिवसीय यात्रा पर बीकानेर पहुंचे।

सर्किट हाउस में चतुर्वेदी की संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर निशांत जैन, सुमन छाजेड़, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह, कोषाधिकारी धीरज जोशी, बीडीए उपायुक्त कुणाल राहड़, श्याम सिंह हाड़ला, दीपक पारीक, राजेन्द्र पंवार समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने अगवानी की।

एडीएम सिटी रमेश देव ने बताया कि प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार चतुर्वेदी बुधवार को दोपहर ढाई बजे कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों की और गुरूवार को सुबह 11.30 बजे शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेंगे।

250 मीटर भूमि के विवाद में अटका 800 मीटर लम्बा नाला

बीकानेर, (कासं)। मानसून की दस्तक में अब महज दो महीने का समय बचा है, लेकिन गंगाशहर क्षेत्र पर इस बार भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लक्ष्मीनाथ घाटी से आने वाले बरसाती पानी समस्या है।

इसके पक्के समाधान के लिए आरयूआईडीपी नाले का निर्माण कर रहा है। यह कार्य पिछले 8 महीनों से सिर्फ 250 मीटर के एक टुकड़े पर आकर रूक गया है। यदि समय रहते यह गतिरोध दूर नहीं हुआ तो सुजानदेसर और ब्राह्मणों के मोहल्ले सहित गंगाशहर के निचले इलाकों में एक बार फिर भारी जलभराव होना तय है। लक्ष्मीनाथ घाटी और मंदिर क्षेत्र के ढलान से आने वाले भारी पानी को आबादी में घुसने से रोकने और सीधे एसटीपी तक पहुंचाने के लिए

- **कुछ स्थानीय निवासियों ने इस जमीन को अपनी मलकियत बताते हुए काम रूकवाया**
- **विभाग ने 550 मीटर नाले का निर्माण तो पूरा कर लिया**

आरयूआईडीपी ने 800 मीटर लम्बे नाले का प्रोजेक्ट शुरू किया था। विभाग ने 550 मीटर नाले का निर्माण तो पूरा कर लिया लेकिन शेष 250 मीटर का काम निजी भूमि के विवाद में उलझ गया है। कुछ स्थानीय निवासियों ने इस जमीन को अपनी मलकियत बताते हुए काम रूकवा दिया है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर नगर विकास न्यास को भी बहुत पहले एक नाला बनाना था, लेकिन वह प्रोजेक्ट फाइलों से बाहर ही नहीं निकल पाया। अब आरयूआईडीपी का प्रोजेक्ट ही अंतिम उम्मीद था, जो जमीनी विवाद में फंसा हुआ है।

गंगाशहर का भूगोल ऐसा है कि लक्ष्मीनाथ मंदिर क्षेत्र का सारा पानी यहां के निचले हिस्सों में जमा हो जाता है। यदि यह 250 मीटर का लिंक पूरा नहीं हुआ तो लाखों की लागत से बना 550 मीटर का नाला भी बेकार साबित होगा। सुजानदेसर और ब्राह्मणों के मोहल्ले के लोग अब भी उसी डर में जी रहे हैं कि दो महीने बाद उनके घरों में फिर से गंदा और बरसाती पानी घुसेगा। मामला गंभीर होते देख जिला कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया है।

पंच गौरव योजना में जिले से करीब साढ़े 10 करोड़ के प्रस्ताव भेजे

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव योजना की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में जिला कलेक्टर को पंच गौरव योजना के जिला नोडल अधिकारी व आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खीचड़ ने बताया कि पंच गौरव योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए जिले से 10 करोड़ 55 लाख 45 हजार के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर अग्रिम कार्यवाही जल्द करवाने हेतु व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए।

उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने जिला कलेक्टर को बताया कि कृषि विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए सर्वाधिक 04

बीकानेर कलेक्टर निशांत जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पंच गौरव योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं। उनमें से 2 करोड़ 30 लाख की लागत से जिले में मोठ महोत्सव का आयोजन, जिला व ब्लॉक पर मोठ को लेकर कार्यशालाएं, वैज्ञानिक कृषक संवाद, प्रशिक्षण, प्रदर्शन इत्यादि के प्रस्ताव शामिल है। साथ ही मोठ प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं।

उद्योग विभाग महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद बीकानेरी नमकीन अंतर्गत उद्योग विभाग ने कुल 2 करोड़ 89 लाख 95 हजार रूपए के प्रस्ताव भेजे हैं। जिनमें से 2 करोड़ 71 लाख की लागत से ग्रामीण हाट बाजार परिसर की मरम्मत व नवीनीकरण का प्रस्ताव शामिल है। उपवन संरक्षक श्री जी. वैंकटेश ने बताया कि एक जिला एक वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा अंतर्गत वन विभाग ने 1 करोड़ 50 लाख के प्रस्ताव भिजवाए हैं। जिनमें से 1 करोड़ 18 लाख की लागत से जिले में रोहिड़ा वाटिका, रोहिड़ा नर्सरी का विकास के साथ साथ इंटरप्रिटेशन सेंटर निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। जिला खेल अधिकारी सुरेन्द्र हर्ष ने बताया कि खेल विभाग ने 98 लाख 50 हजार के प्रस्ताव भिजवाए हैं। जिनमें से 50 लाख की लागत से तीरंदाजी खेल मैदान का विकास व 35 लाख की लागत से तीरंदाजी से जुड़े खेल उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव शामिल है।

जनगणना कार्य से मुक्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी ने जिला परिषद सीईओ शैलजा पांडे से मुलाकात की।

पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया और ग्रामीण विकास व अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की पंचायत समितियों में कार्यरत दो ग्राम विकास अधिकारियों को जनगणना कार्य से विमुक्त करने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की नियमित उपस्थिति आवश्यक है।

प्रतिनिधिमंडल ने एसीईओ दिलीप कुमार और प्रियंका तलानिया से भी मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। सीईओ शैलजा पांडे ने समस्याओं पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान जिलाध्यक्ष रामनिवास भादू, जिला मंत्री रामनिवास सारण मौजूद थे।

SBI Life
अपने लिए, अपनों के लिए.
सूचना
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) एतद्वारा व्यवसायिक भवन, लीज आधार पर भूस्वामियों से निम्न व्यापक संभावनाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव निविदाएं आमंत्रित करता है।
1. भवन सभी ऋण भार से स्वतंत्र एवं तुरंत कब्जे हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
2. भवन कामर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन की व्यवस्था सहित व्यावसायिक भवन होना चाहिए एवं अग्निशमक एनओसी, व्यवसायिक सर्टिफिकेट, भवन का बीमा जिसमें समुचित और बाधा रहित बिजली एवं जल वितरण, साइनेज का स्थान, पार्किंग एवं आधुनिक फायर फाईटिंग सिस्टम, कारों की पर्याप्त पार्किंग इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।
3. परिसर श्रीगंगानगर के प्रमुख क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
4. भवन का कॉरपेट एरिया लगभग 2891 वर्गफिट होना चाहिए।
इच्छुक निविदाकर्ता निविदा का प्रारूप को हमारी वेबसाइट www.sbilife.co.in (https://www.sbilife.co.in/en/services/download-centre- RFP forms) से प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तकनीकी निविदा एवं प्राइस बिड अलग-अलग सील बंद लिफाफो में "दी रीजनल डायरेक्टर, जयपुर, एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, एआरजी कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नंबर 8 एवं 9, गोपालबाडी, जयपुर, राजस्थान - पिन - 302001", फोन : 0141-4256600 दिनांक 27.05.2026 तक या पहले पहुँच जाने चाहिए।
एसबीआई लाइफ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
दिनांक:- 13.05.2026 स्थान- जयपुर
उक्त प्रदर्शित किया गया ट्रेड लोगों भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है तथा लाइसेंस के अंतर्गत एसबीआई लाइफ द्वाराउपयोग किया जा रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय: नटराज, एमवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 आईआरडीएआई पंजीकरण सं. 111, सीआईएन: L99999MH2000PLC129113 वेबसाइट: www.sbilife.co.in ई-मेल: info@sbilife.co.in टॉल फ्री नं.: 1800 267 9090 (ग्राहक सेवा समय : 24X7)

SBI Life
अपने लिए, अपनों के लिए.
सूचना
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) एतद्वारा व्यवसायिक भवन, लीज आधार पर भूस्वामियों से निम्न व्यापक संभावनाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव निविदाएं आमंत्रित करता है।
1. भवन सभी ऋण भार से स्वतंत्र एवं तुरंत कब्जे हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
2. भवन कामर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन की व्यवस्था सहित व्यावसायिक भवन होना चाहिए एवं अग्निशमक एनओसी, व्यवसायिक सर्टिफिकेट, भवन का बीमा जिसमें समुचित और बाधा रहित बिजली एवं जल वितरण, साइनेज का स्थान, पार्किंग एवं आधुनिक फायर फाईटिंग सिस्टम, कारों की पर्याप्त पार्किंग इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।
3. परिसर सूरतगढ़ के प्रमुख क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
4. भवन का कॉरपेट एरिया लगभग 2109 वर्गफिट होना चाहिए।
इच्छुक निविदाकर्ता निविदा का प्रारूप को हमारी वेबसाइट www.sbilife.co.in (https://www.sbilife.co.in/en/services/download-centre- RFP forms) से प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तकनीकी निविदा एवं प्राइस बिड अलग-अलग सील बंद लिफाफो में "दी रीजनल डायरेक्टर, जयपुर, एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, एआरजी कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नंबर 8 एवं 9, गोपालबाडी, जयपुर, राजस्थान - पिन - 302001", फोन : 0141-4256600 दिनांक 27.05.2026 तक या पहले पहुँच जाने चाहिए।
एसबीआई लाइफ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
दिनांक:- 13.05.2026 स्थान- जयपुर
उक्त प्रदर्शित किया गया ट्रेड लोगों भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है तथा लाइसेंस के अंतर्गत एसबीआई लाइफ द्वाराउपयोग किया जा रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय: नटराज, एमवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 आईआरडीएआई पंजीकरण सं. 111, सीआईएन: L99999MH2000PLC129113 वेबसाइट: www.sbilife.co.in ई-मेल: info@sbilife.co.in टॉल फ्री नं.: 1800 267 9090 (ग्राहक सेवा समय : 24X7)

राजस्थानी भाषा को लेकर व्यापक नीति बनाएं राजस्थान सरकार - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये कि राजस्थान सरकार सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाएं

- **कोर्ट ने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूली स्तर पर इसे लागू करने में देरी क्यों?**
- **सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने को कहा है**
- **शुरुआत में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्तर पर राजस्थानी को माध्यम या विषय के रूप में जोड़ा जाए, फिर धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं में भी अनिवार्य किया जाए**

जोधपुर, (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूली स्तर पर इसे लागू करने में देरी क्यों?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह संवैधानिक अधिकारों के हनन पर मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। बेंच ने कहा कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी 2020) का मूल मंत्र है, जिसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने को कहा है। शुरुआत में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्तर पर राजस्थानी को माध्यम या विषय के रूप में जोड़ा जाए, फिर धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं में भी अनिवार्य किया जाए।

यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान के हर प्राइवेट स्कूल के लिए भी बाध्यकारी होगा। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि रीट के सिलेबस में भी राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट के इस रुख के बाद अब राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य हो सकता है। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। लंबे समय से राज्य सरकार यह तर्क देती रही थी कि राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसे स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने ढर्रे वाली सोच को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षिणक मान्यता के लिए 8वीं अनुसूची का इंतजार करना तर्कहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सितंबर 2026 में फिर से लिस्ट किया है। तब तक राजस्थान सरकार को कोर्ट को यह बताना होगा कि उन्होंने इस आदेश को लागू करने के लिए क्या नीति बनाई है और स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने की तैयारी कहां तक पहुंची है।

अजमेर में एक करोड़ की चरस के साथ दो नेपाली तस्कर गिरफ्तार

एटीएस की सूचना पर अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई की

- **पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चरस की खेप लेकर बस के जरिए नेपाल से भारत पहुंचे और फिर अलग-अलग साधनों से होते हुए अजमेर आए थे**
- **प्रारंभिक जांच के अनुसार ये तस्कर नेपाल से मादक पदार्थ लाकर भारत के विभिन्न शहरों में सप्लाई करने का काम करते हैं**
- **पुलिस जांच कर रही है कि अजमेर में यह डिलीवरी किसे दी जानी थी**

अजमेर, (कासं)। अजमेर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों के पास से दो किलो उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सिटी हिंमाशू जांगिड़ ने बताया कि एटीएस से इनपुट मिला था कि नेपाल से दो युवक चरस की बड़ी खेप लेकर अजमेर आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने एमडीएस यूनिवर्सिटी तिराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान रोडवेज बस से उतरे दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने संदिग्धों को घेरकर तलाशी ली तो उनके पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नेपाल निवासी खेमकुमार पुत्र भीमसारु तथा अजय राणा पुत्र महरमान राणा है।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चरस की खेप लेकर बस के जरिए नेपाल से भारत पहुंचे और फिर अलग-अलग साधनों से होते हुए अजमेर आए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये तस्कर नेपाल से मादक पदार्थ लाकर भारत के विभिन्न शहरों में सप्लाई करने का काम करते हैं।

हिमांशु जांगिड़, एडिशनल एसपी सिटी अजमेर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि अजमेर में यह डिलीवरी किसे दी जानी थी और इस गिरोह के तार और कहां जुड़े हैं।

टोंक में 10 अवैध हथियार जब्त, पांच जनों को पकड़ा

उनियारा पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, बारूद और छर्रे बरामद किये।

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उनियारा वृताधिकारी के नेतृत्व में उनियारा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार, बारूद और छर्रे बरामद कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान 10 अवैध हथियार जब्त किए गए, इनमें 6 देशी टोपीदार बंदूकें, 1 देशी कट्टा और 3 एयरगन शामिल हैं। इसके अलावा, भारी मात्रा में गन पाउडर (बारूद), 20 मोटे छर्रे, 655 मध्यम छर्रे और 100 एयरगन पैलेट्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना बनेठा और थाना उनियारा क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से दबिश दी। बनेठा थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 मामले दर्ज किए गए, जबकि उनियारा थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जोधपुर में घर में घुसकर महिलाओं के गहने लूटे

जोधपुर, (कासं)। शहर के कुड़ी भगतासनी क्षेत्र सेक्टर 12 में घर में घुसकर अपहरण का प्रयास करने के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने घर की महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया और वहां से सोने-चांदी के गहने ले गए। पीड़ित की तरफ से विवेक विहार थाने में एससी-एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।

विवेक विहार थाना पुलिस ने बताया कि 11 मई की रात को सेक्टर 12 में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में कुछ लोगों ने प्रवेश कर उसके अपहरण का प्रयास किया। बीच-बचाव में आई महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। आरोपी घर से सोने-चांदी की चेन के साथ चांदी के अंगूठियां और 12800 रूपए लूट कर ले गए। प्रकरण में एसीपी स्तर के अधिकारी की तरफ से जांच की जा रही है।

पात्रता जांच हेतु विचारित सूची जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-प्लांट पैथोलॉजी (कृषि विभाग) भर्ती-2024 के तहत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी कर दी गई है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम के आधार पर 12 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु विचारित सूची में शामिल किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह विचारित सूची केवल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जारी की गई है। इसे अंतिम चयन या वरीयता सूची नहीं माना जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची कृषि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के बाद आयोग जारी करेगा।

डॉ. भुवनेश जैन को ''मुंणोत नैणसी मारवाड़ रत्न सम्मान'' से सम्मानित किया

जोधपुर के 568 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 19 प्रतिभाओं का सम्मान किया

जोधपुर में बाड़मेर के पर्यावरण, संस्कृतिकर्मी एवं लेखक डॉ. भुवनेश जैन को सम्मानित किया गया।

जयपुर/जोधपुर। जोधपुर के 568 वें स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में मंगलवार को आयोजित मारवाड़ रत्न समारोह में बाड़मेर के पर्यावरण, संस्कृतिकर्मी एवं प्रख्यात लेखक डॉ. भुवनेश जैन को मुंणोत नैणसी मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व महाराजा गज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में अतिथियों ने भुवनेश जैन को शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र और नकद 51 हज़ार रूपये की राशि से पुरस्कृत किया। यह मारवाड़ रत्न पुरस्कार डॉ. जैन को उनकी प्रखर लेखनी से मारवाड़ की लोक संस्कृति, ओरण व थार के पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी भील, हस्तशिल्प एवं कलात्मक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाने और समाचार पत्रों में शोधपूर्ण लेखों द्वारा मरुधरा की सांस्कृतिक परम्पराओं के उत्कृष्ट संरक्षण तथा योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस अवसर पर धनाऊ की झीमा देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 19 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।

डॉ. जैन ने वर्ष 1989-90 से ओरण - गोचर सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, जन जागरण एवं पैरवी का कार्य शुरू किया था। उनके प्रयासों से अकेले बाड़मेर में 250 से अधिक अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र वर्तमान मे मेरा युवा भारत के निदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. जैन का नियमित रूप से प्रखर लेखन कार्य आज भी जारी है। जैन ने पर्यावरण के साथ लोक संस्कृति संरक्षण एवं लेखन, रेगिस्तानी आदिवासी भील इतिहास, संस्कृति, थार के हस्तशिल्प पर शोधपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉ. जैन की पहचान ओरण दूत, ओरण मैन के रूप में रही है। वर्तमान में डॉ. जैन सोसाइटी टु अपलिफ्ट रूरल इकोनामी नामक संस्था से जुड़े हैं। डॉ. जैन को मारवाड़ रत्न अवार्ड पर पर्यावरण प्रेमियों, लोक कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है।

अलवर : यूआईटी और निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

अलवर, (निसं)। लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के चलते एसीजेएम कोर्ट ने अब यूआईटी और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कोर्ट ने कलैक्टर कार्यालय व उनकी कार को कुर्क करने के आदेश दिए थे।

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता तरुण सैनी ने बताया कि यूआईटी मामले में खांचा भूमि सुंदरलाल सैनी को देने के आदेश पूर्व में जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद करीब ढाई साल तक यूआईटी यह कहती रही कि संबंधित डॉक्यूमेंट नगर निगम को सौंप दिए गए हैं। आरोप है कि न्यायालय ने 1207 खसरा नंबर को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने 674 और 676 खसरा नंबर की रिपोर्ट दर्ज कराकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। मामले में न्यायालय ने जिला कलैक्टर अर्तिका शुक्ला को भी कई बार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नगर निगम की ओर से भी मामले में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अब यूआईटी और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला खांचा भूमि आवंटन नहीं करने का है।

बीकानेर में पुलिस ने मध्य प्रदेश के हथियार तस्कर को पकड़ा

- **दो पिस्टल और दस जिंदा कारतूस बरामद, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस**
- **आरोपी को श्रवण सोडा गैंग का मुख्य हथियार सप्लायर बताया जा रहा है**

बीकानेर, (निसं)। पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को श्रवण सोडा गैंग का मुख्य हथियार सप्लायर बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में डीएसटी और बीछवाल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। गिरफ्तार आरोपी शिवा निवासी बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी हाल ही में अवैध पिस्टल तस्करी के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही फिर से हथियार तस्करी में सक्रिय हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2025 में खाजूवाला क्षेत्र में सामने आए पिस्टल तस्करी प्रकरण में भी आरोपी जेल जा चुका है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में किन-किन लोगों से संपर्क थे और अवैध हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है। पुलिस को सायबर सेल से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सायबर सेल के एएसआई दीपक यादव की सूचना पर डीएसटी और थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगठित अपराध और नए कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह हथियार कहां से लाता था और किन अपराधियों तक सप्लाई करता था। बीकानेर पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियार तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट की मथानिया और कुड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर टोपीदार बंदूक एवं चाकू बरामद किया। दोनों के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट में प्रकरण बनाए गए हैं। वहीं पुलिस ने आगे की जांच शुरु कर दी है।

मथानिया पुलिस थाने के एएसआई सोहनलाल ने जुगत सिंह नगर बालरवा गांव में दबिश देकर एक ट्यूबवैल पर रहने वाले बिरमाराम पुत्र बंशीलाल से टोपीदार बंदूक को जब्त कर ऑर्म्स एक्ट में मामला बनाया। वहीं दूसरी तरफ कुड़ी भगतासनी थाने के एएसआई महेंद्र कुमार ने राजीव गांधी कच्ची बस्ती क्षेत्र में भूराराम पुत्र सुकाराम को पकड़ा और धारदार चाकू बरामद किया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

एनजीटी के सख्त निर्देश के बाद भी सांभर झील में वाटर स्टोरेज के लिए हो रही है खुदाई

- **एनजीटी की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि इस परिक्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि संचालित ना की जाए जो परिंदों की संवेदनशीलता को डिस्टर्ब करें**

सांभर साल्टस लिमिटेड अपने फायदे के लिए कुछ मीटर की दूरी पर ही जेसीबी से खुदाई करवाकर वाटर स्टोरेज के लिए एक वृहद तालाबनुमा गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

सांभरझील, (निसं)। रामसर साइट में दर्ज विश्व नम भूमि का दर्जा प्राप्त लवणीय झील में वर्तमान में हजारों की तादाद में फ्लेमिंगो पक्षियों का इस भीषण गर्मी में भी जमावड़ा इस बात का स्पष्ट सबूत है कि इन परिंदों को यहां का वातावरण माफिक आ गया है। शीतकालीन सत्र में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां आकर यह अपने प्रजनन की क्रिया को अंजाम देते हैं, अंडों की सुरक्षा करते हैं तथा बच्चों के बाहर आने का इंतजार करते हैं, इनके बड़े होने तक मादा फ्लेमिंगो उनकी पूरी सुरक्षा करती है। ऐसे में इन बच्चों के बड़ा होकर उड़ने लायक होने तक फ्लेमिंगो यहीं पर बैठे रहते हैं और यह सिलसिला प्रतिवर्ष इसी प्रकार चलता है। यह सब संज्ञान में होने के बावजूद सांभर साल्टस लिमिटेड अपने फायदे के लिए कुछ मीटर की दूरी पर ही जेसीबी से खुदाई करवाकर वाटर स्टोरेज के लिए एक वृहद तालाबनुमा गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में एनजीटी की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि इस परिक्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि संचालित ना की जाए जो परिंदों की संवेदनशीलता को डिस्टर्ब करें, राज्य सरकार को भी इसकी पालना सुनिश्चित किए जाने के लिए पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण पशु विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त कर उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल को पत्र लिखकर तुरंत एक्शन लिए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने एसडीएम को बताया कि वर्तमान में इस जगह खसरा संख्या 1295/1275, ग्राम झपोक, शाकंभरी माता, मंदिर रोड़, सांभरलेक के सामने इलेक्ट्रिसिटी लाइन के नजदीक जेसीबी की सहायता से कुछ कार्मिकों द्वारा खुदाई एवं मिट्टी हटाने एवं स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है, जिस स्थान पर जेसीबी मशीन से खुदाई एवं मिट्टी हटाने का कार्य चल रहा है उस के पीछे की तरफ़ फ़्लैमिंगो जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, बैठे हुए देखे जा सकते हैं। यहीं पर इस अवधि के दौरान क्योंकि यह प्रजनन काल का समय है तो संभवतया ये पक्षी घोंसलों का निर्माण कर रहे हों सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र इस कार्य को रुकवा कर संकटग्रस्त प्रजाति फ़्लैमिंगो को प्रजनन हेतु में प्राकृतिक वातावरण दिया जाए तथा इस प्रक्रिया में बाधा बनने जा रहे इस कार्य को तुरंत रुकवाया जाए। ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र में जहाँ अभी यह कार्य चल रहा है, पूर्व में कभी भी नमक निर्माण क्यार इत्यादि नहीं बनाये गए हैं। पूर्व में इस स्थान पर ट्यूबवैल की भी खुदाई का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध से बंद करना पड़ा था।

2.62 लाख का गांजा जब्त, आरोपी को पकड़ा

चूरू, (कासं)। पुलिस ने 2 लाख 62 हजार 800 रूपये 5.256 किलोग्राम अवैध गांजा जप्त किया। साथ ही युवाओं में नशा फैलाने से पूर्व ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू, निश्चय प्रसाद एम.ने बताया कि पुलिस थाना सुजानगढ़ पर अलग-अलग टीमें गठित की गयी, गठित टीम प्रभारी रामस्वरूप उनि मय टीम को मेगा हाईवे पर गस्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने साथ कट्टे में अवैध गांजा ले जा रहा है, जिस पर मुखबीर ईतला के मुताबिक मेगा हाईवे से मांडेता रोड़ पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको काबू किया, एवं चैक किया जाकर उसके कब्जा से कट्टा में अवैध गांजा जप्त कर आरोपी प्रकाश जाट पुत्र चुन्नीलाल को गिरफ्तार किया गया।

उदयपुर में एक लाख की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार

- **डेथ क्लेम पास करने के एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी**

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईटेलिजेंस उदयपुर की टीम ने राज्य बीमा व प्रावधायी विभाग के यूडीसी शेखर मथूरिया को डेथ क्लेम पास करने के एवज में पीड़ित से एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी मुख्यालय के निर्देश परभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलीजेंस यूनिट उदयपुर ने कार्यवाही करते हुए आरोपी शेखर मथूरिया हॉल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग उदयपुर को एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महाानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो की इंटेलिजेंस युनिट उदयपुर को शिकायत मिली कि परिवादी की भांजी सरकारी शिक्षिका की मृत्यु होने पर राज्य बीमा के डेथ क्लेम को पास करने एवं कमियों की पूर्ति कर ज्यादा क्लेम राशि पास करवाने की एवज में पहले आरोपी द्वारा 7 लाख 50 हजार रूपये की मांग की गई एवं 11 मई को आरोपी द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेने की सहमति हुई। इस पर 12 मई को रिश्वत की प्रथम किश्त एक लाख रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिस पर ब्यूरो टीम ने आरोपी शेखर मथुरिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

राज्य बीमा व प्रावधायी विभाग में कार्यरत आरोपी वरिष्ठ सहायक शेखर मथूरिया।

आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती में न्याय की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाया

होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन किया।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाते हुए सरकार से निष्पक्ष समाधान की मांग उठाई। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में जिला स्तर पर भी विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

■ **प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं हो सकी**

धरने में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभाग को कई बार अवगत कराया था कि अलग-अलग पद्धितयों के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर समान रखना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद एक ही चयन प्रणाली लागू की गई, जिससे कई योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं हो सकी। वहीं विभिन्न पद्धितयों में अलग-अलग प्रश्न हटाए जाने से करीब 6 प्रतिशत तक अंकों का असंतुलन पैदा हो गया, जिससे हजारों होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है।अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा कर पद्धितवार पद वर्गीकरण लागू किया जाए। ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

एसआई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एसआई भर्ती: 2021 पेपर लीक के मास्टर माइंड जगदीश विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने के मामले में जगदीश विश्नोई को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की उस एसएलपी पर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के 16 जनवरी 2026 के उसे जमानत देने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। एसएलपी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय एवं एएजी शिव मंगल शर्मा ने कहा कि जगदीश विश्नोई 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े संगठित पेपर लीक रैकेट का एक प्रमुख मास्टरमाइंड एवं किंगपिन रहा था। राजस्थान एटीएस एवं एसओजी की गई जांच के अनुसार, आरोपी ने अन्य सह-आरोपियों एवं सेंटर सुपरिंटेंडेंट राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर व्हाट्सएप के जरिए 10 लाख रुपए में गोपनीय पेपर पहले से प्राप्त किए, उन्हें हल करवाया और बाद में भारी धनराशि लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। जिन 25 अभ्यर्थियों को लीक पेपर मुहैया कराए गए थे, उनका भी भर्ती में चयन हुआ है। जांच के दौरान आरोपी से एक अकाउंट डायरी बरामद हुई, जिसमें अभ्यर्थियों एवं धन लेन-देन का विवरण दर्ज था।

■ **आरोपी 2008 से ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है , उसके खिलाफ समान प्रकृति के 13 अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं**

एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि डायरी में लिखावट जगदीश विश्नोई की ही थी। आरोपी 2008 से ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ समान प्रकृति के 13 अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में 3 मार्च 2024 को पुलिस थाना एटीएस एवं एसओजी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420 एवं 120-बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत दर्ज की गई थी।

सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत,चार घायल

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में मंगलवार सुबह हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर जा रही तेज रफ्तार निजी बस ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें एक वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

अचरोल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि चंदवाजी निवासी शेर सिंह अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए मोटरसाइकिल से कूकस जा रहा था। इसी दौरान गलत दिशा में कट लेते समय बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के नीचे जा घुसी और परिवार सड़क पर दूर तक जा गिरा।

टीम ने दूध की गुणवत्ता जांचकर लिए सैंपल

जयपुर। राज्य सरकार के शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर द्वितीय क्षेत्र में दूध के विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। यह अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने चाकसू, कोथून, बाड़ा पदमपुरा और शिवदासपुरा क्षेत्र में विभिन्न दूध संकलन केंद्रों और बीएमसी फर्म्स का निरीक्षण किया।दूध के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। लैब से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पांडुलिपियाँ पर पांच दिवसीय पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में मंथन

हरिद्वार/जयपुर । भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल 'ज्ञानभारतम् मिशन' के अंतर्गत 'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार में किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की विशाल एवं अमूल्य पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण करना है, ताकि यह प्राचीन ज्ञान-संपदा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।

■ **पांडुलिपियाँ मानव गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हैं : ज्ञान भारतम् मिशन**

'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला का आयोजन पांडुलिपि संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा संरक्षण एवं भंडारण संबंधी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत शॉल, माला एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर किया गया।

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉ. अनुपम श्रीवास्तव ने 'फ्लोरा' की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पौधों का व्यवस्थित वैज्ञानिक विवरण होता है, जो पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वैज्ञानिक दस्तावेज जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

योजना के चौथे चरण में राजस्थान को मिली 1216 सड़कें

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सशक्त गांव, विकसित भारत' के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ग्रामीण परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी एक सशक्त माध्यम बन रही है।

■ **तीसरे चरण में प्रदेश में बनी 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सुदृढ़ सड़कें, मार्च 2028 तक बढ़ी योजना की अवधि**

केन्द्र सरकार ने इस योजना के चौथे चरण (पीएमजीएसवाई-चतुर्थ) के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान देशभर में 62 हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के साथ कुल 70 हजार 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस चरण में 2011 की जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर अलग-थलग पड़ी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी। इसमें विशेष श्रेणी के क्षेत्रों - जनजातीय (पांचवीं अनुसूची) क्षेत्र, आकांक्षी जिले-ब्लॉक और मरुस्थलीय क्षेत्र पर फोकस रखा गया है। राजस्थान के मरुस्थलीय और दूरस्थ गांवों को भी चतुर्थ चरण में बड़ी सौगात मिली है। चौथे चरण में देशभर में अब तक स्वीकृत 4 हजार 795 सड़कों में से प्रदेश को 1 हजार 216 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो संख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसमें 15 हजार 401 किलोमीटर सड़क में से 3 हजार 219 किलोमीटर लम्बी सड़कें राजस्थान के लिए स्वीकृत हुई हैं और इस मामले में राजस्थान जम्मू-कश्मीर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के लिए 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में लगभग 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

बदनामी के डर से सरकार ने दबाई नीट पेपर लीक की बात : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने परीक्षा रद्द होने और इसकी जांच को सौंपे जाने के बाद भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि इस पूरे प्रकरण में संगठित स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 22-23 लाख मेहनती विद्यार्थियों के सपनों और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।

जूली ने कहा कि इस मामले का महत्वपूर्ण पहलु यह है कि अभियर्थियों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद जैसा की जानकारी मिल रही है, मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया और फिर इसे दबाने की कोशिशें हुई , एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई लेकिन अब परीक्षा कराने वाली संस्था ने पेपर लीक के कारण इसे रद्द कर दिया है तो साफ़ है कि भाजपा सरकार ने कितनी गैर जिम्मेदारना हरकत की है। जूली ने आंकड़ों के साथ प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासन में अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं, जो भाजपा की कार्यशैली की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है।

■ **'पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज न करना गैर जिम्मेदाराना हरकत'**

■ **भाजपा के 10 वर्षों के शासन में अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं**

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर चुनाव और मंच से भाजपा बड़े-बड़े वादे करती है और सख्त कार्रवाई के खोखले दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत यह है कि भाजपा सरकार युवाओं की मेहनत और उनके समय की चिता जलाकर उस पर अपनी सियासत की रोटियां सेक रही है। पेपर लीक अब भाजपा की पहचान बन चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सच्चाई को उजागर कर दोषियों पर नकेल कसने के बजाय, पूरे मामले को रफा-दफा करने और दबाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी बदनामी के डर से और अपनी छवि को चमकता हुआ दिखाने के लिए सरकार ने दो हफ्तों तक लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाए रखा। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह भाजपा की सुनियोजित गैर-जिम्मेदारी और युवाओं के प्रति उनकी संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है। जूली ने आगे कहा कि पहले भी शीट में हुई गड़बड़ियों के मामलों में इसी तरह सच्चाई को दफन करने की कोशिश की गई थी।

इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता देश का युवा, न्याय या पारदर्शिता नहीं है, बल्कि केवल और केवल अपना फेस सेविंग है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस संगठित अपराध के असली आकाओं को बेनकाब नहीं किया जाता और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक युवाओं की आवाज बुलंद करती रहेगी।

हाईकोर्ट में मोबाइल रिकार्डिंग की सुनवाई हुई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में अदालती कार्रवाई को मोबाइल में रिकार्डिंग करने को गंभीर मानते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल जब्त कर लिया। वहीं अशोक नगर थाना पुलिस को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले में प्रार्थी कमल राठौड़ व रिकॉर्डिंग करने वाले उसके ड्राइवर अनिल सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह मामला एक्टिंग सीजे के समक्ष रखा जाए, ताकि इन याचिकाओं को मौजूदा बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश कमल राठौड़ की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में की गई अवमानना ऐसी प्रकृति की है जो न्याय की प्रक्रिया में दखल करती है। सुनवाई की रिकार्डिंग अवमानना है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में दखल के साथ ही न्यायालय की गरिमा को भी कम करती है। दरअसल आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने देखा कि एक व्यक्ति बिना मंजूरी के अदालती कार्रवाई की अपने मोबाइल में रिकार्डिंग कर रहा है। जब उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वह रिकार्ड की गई कार्रवाई को डिलीट करने लगा। जब उसे बुलाकर पूछा कि वह अदालती कार्रवाई रिकार्ड क्यों कर रहा है, उसने बताया कि वह प्रार्थी कमल राठौड़ का ड्राइवर है और उसी के मामले की रिकार्डिंग कर रहा है। अदालत ने इसे न्यायालय प्रक्रिया में दखल मानते हुए कहा कि यह अवमानना है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2020 के भी न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने पर प्रतिबंध है।

■ **हाईकोर्ट ने पुलिस थाने को कानूनी कार्रवाई के निर्देश**

■ **हाईकोर्ट ने एक मामले में अदालती कार्रवाई को मोबाइल में रिकार्डिंग करने को गंभीर मानते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल जब्त**

35 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई हुई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) गुलाबी नगरी जयपुर के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर सक्रिय है। वर्ष 2026 के दौरान जनवरी से मई माह तक जेडीए द्वारा दैनिक जनसुनवाई करते हुए अब तक लगभग 35 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह में 8,859 फरवरी माह में 8,587 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्च में 6,686 वहीं अप्रैल माह में 7,837 मामलों की सुनवाई की गई । मई माह में अब तक लगभग 3,026 परिवादों की सुनवाई की गई है जिनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जा रहा है । सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता, और समयबद्धता के साथ स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

सार-समाचार

ज्वैलरी शॉप से सवा तीन लाख का सोना लेकर बदमाश फरार

जयपुर। झोटवाड़ा थाना इलाके में लता सर्किल स्थित एक ज्वैलरी शॉप पर दिनदहाड़े चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत फैल गई। ग्राहक बनकर आए एक शातिर युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 3.25 लाख रुपए कीमत का पक्का सोना चोरी कर लिया और फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार गणपति ज्वैलर्स के संचालक शंकर सोनी ने बताया कि 10 मई को दोपहर करीब 1:38 बजे एक युवक दुकान पर आया और पहले चांदी का ताबीज खरीदा। इसके बाद उसने सोने का भाव पूछते हुए 100 मिलीग्राम पक्का सोना दिखाने की बात कही। दुकानदार जब उसे सोना दिखा रहा था, तभी आरोपी ने कान की बालियां देखने की मांग की। दुकानदार के नीचे झुकते ही आरोपी ने हाथ की सफाई दिखाते हुए पक्के सोने से भरी डिब्बी गायब कर दी। बताया जा रहा है कि डिब्बी में करीब 20 ग्राम वजन के 4 से 5 सोने के टुकड़े रखे थे, जिनकी कीमत लगभग सवा तीन लाख रुपए है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज में आरोपी की गतिविधियां स्पष्ट नजर आई हैं, जिसके आधार पर उसकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने बाजारों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक 18 मई को

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आगामी 18 मई 2026 को जयपुर स्थित गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी मांगों पर अपनाए जा रहे उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश महामंत्री मोहन लाल शर्मा ने संयुक्त बयान में बताया कि वर्तमान में योजना में आ रही समस्याओं और समर्पित अवकाश (सरेंडर लीव) के भुगतान पर लगी अघोषित रोक से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर की विसंगतियों तथा समर्पित अवकाश के भुगतान न होने को लेकर कड़ा विरोध जताया जा चुका है। महामंत्री मोहनलाल शर्मा ने कहा की बजट घोषणा के अनुसार पदोन्नितयों के आदेश जारी करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अनुभव में दो वर्ष की छूट के आदेश जारी करने, ठेका कार्मिकों के लिए का गठन करने सहित महासंघ (एकीकृत) के लंबित 25 सूत्रीय मांगपत्र पर आज दिनांक तक कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होने एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेना सरकार की कर्मचारी विरोधी मंशा को दर्शाता है।

संदिग्ध हालात में महिला की मौत

जयपुर। मुरलीपुरा थाना इलाके की जीवन दीप कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मकान से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहां महिला का शव पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मृतका की पहचान टोंक जिले के बरौनी निवासी अंबिका के रूप में की। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि अंबिका फरवरी माह में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर राम कल्याण गुर्जर के साथ चली गई थी। इसके बाद दोनों ने 3 मई को मुरलीपुरा क्षेत्र में किराए का मकान लिया था। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट पर रामकल्याण गुर्जर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

नाले में मिला व्यक्ति का शव

जयपुर। शास्त्री नगर थाना इलाके में मंगलवार शाम राणा कॉलोनी और व्यास कॉलोनी के बीच बने नाले में एक व्यक्ति का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

राज्य में डेयरी विस्तार के लिए मुख्य परियोजनाओं को केन्द्र की सहमति

जयपुर। राज्य के डेयरी क्षेत्र में विस्तार और आरसीडीएफ के सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की परिकल्पना बहुत जल्द साकार होगी। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में जयपुर में आज हुई बैठक में भारत सरकार ने आरसीडीएफ को 1500 करोड रूपये की सहायता उपलब्ध कराने पर सैद्धान्तिक सहमति दी है। भारत सरकार की जीका (जापान इन्टरनेशनल कॉर्परेशन एजेन्सी) परियोजना के अन्तर्गत 1000 करोड और एनपीडीडी (नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डवलपमेन्ट) परियोजना के अन्तर्गत 500 करोड रूपये की सहायता पर सहमति दी गई है। इस राशि से आरसीडीएफ के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में विस्तार होगा। आरसीडीएफ में वर्तमान में संकलित हो रहे 45 लाख लीटर प्रतिदिन को बढाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन किया जायेगा। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में 20 लाख लीटर प्रतिदिन की बढोतरी की जायेगी।

■ **बैठक में सरकार ने आरसीडीएफ को 1500 करोड रूपये की सहायता उपलब्ध कराने पर सैद्धान्तिक सहमति दी**

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक ली।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में हुई दो राज्य स्तरीय बैठको में लिये गये निर्णयों की क्रियान्वति को मूर्त रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष संख्या 1 में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सरस को केवल डेयरी सहकारी संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत एवं व्यापक राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होने राज्यभर में सरस आउटलेट एवं डेयरी पार्लरों का विस्तार करने, नये प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करने तथा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढने के निर्देश दिये।

भूमाफिया पर कार्रवाई करने वालो पर गिरी गाज, मामला डीजीपी तक पहुंचा

जयपुर। राजधानी के टोंक रोड स्थित वसुंधरा कॉलोनी में करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई होने से मामला तूल पकड़ गया है। भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ कार्रवाई करने वाली बजाज नगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एसीपी मालवीय नगर, एसीपी सदर और बजाज नगर थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बजाजनगर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

■ **100 करोड़ रुपए मूल्य की एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई होने से मामला**

जानकारी के अनुसार वसुंधरा कॉलोनी में सत्यनारायण मीणा की करीब एक बीघा भूमि पर बनी दुकानों और मकानों पर 30 मार्च 2026 को भूमाफिया आशीष अग्रवाल ने अशोक नगर थाने के हिस्ट्रीशीटर कपिल शर्मा और उसके साथियों के जरिए कथित रूप से ताले तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर मालवीय नगर एसीपी के निर्देशन में बजाज नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और तीन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्रीशीटर कपिल शर्मा भी शामिल था।

पुलिस की इस कार्रवाई को प्रारंभिक तौर पर प्रभावी माना गया, लेकिन बाद में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कार्रवाई की प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं को लेकर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। सूत्रों के अनुसार इसी घटनाक्रम के बाद पुलिस आयुक्त ने बजाज नगर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई।

वहीं मामला अब डीजीपी स्तर तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

टोंक में आईपीएल मैच पर एक करोड़ का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा, तीन गिरफ्तार

पंजाब-दिल्ली आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में चलाये गये विशेष अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हुए सोमवार रात्रि को सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे-52 के पास स्थित मालिक भागचंद गुर्जर के फार्म हाउस पर पंजाब-दिल्ली आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए डीएसटी ने एक करोड़ का ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा पकड़ा तथा मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए हैं।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीएल क्रिकेट मैचों पर चल रहे ऑनलाइन सट्टे के मामले डीएसटी ने कार्यवाही करते हुए करीब एक करोड़ रुपए से ज्यादा के हार-जीत के हिसाब का खुलासा किया है।

पुलिस ने लैपटॉप, टैबलेट, एलईडी टीवी, 9 मोबाइल और डायरियां जब्त की।

सोमवार देर रात सदर थाना क्षेत्र में एनएच-52 के पास स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से लैपटॉप, टैबलेट, एलईडी टीवी, 9 मोबाइल फोन, जिओ वाई-फाई सिस्टम, कार और क्रिकेट सट्टे से जुड़ी डायरियां जब्त की गई हैं, जिनमें करीब एक करोड़ रुपए से ज्यादा की हार-जीत का रिकॉर्ड दर्ज मिला। सूचना के बाद जिला स्पेशल टीम ने मौके से आरोपी वकुल उर्फ बिन्नी पुत्र प्रकाश निवासी तनेजा ब्लॉक आदर्श नगर जयपुर, अमित पुत्र हीरालाल पंजाबी निवासी श्रीराम रेजिडेंसी सिरसी रोड जयपुर और फार्म हाउस मालिक भागचंद गुर्जर पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी बंबोर गेट टोंक को गिरफ्तार किया है। जिला स्पेशल टीम ने जब्त सामान और आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जांच कर रही है।

■ पुलिस ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जांच कर रही है

खेतड़ी में वन विभाग की टीम पर हमला, तीन गिरफ्तार

राजकार्य में बाधा पहुंचाकर मारपीट करने, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में की कार्रवाई

■ 22 अप्रैल को गांव कालोटा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन किए जाने की सूचना मिलने पर वन एवं खनन विभाग की टीम जांच के लिये गई थी

खेतड़ी, (निसं)। बबाई पुलिस ने मंगलवार को वन विभाग की टीम पर हमला करने के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को गांव कालोटा क्षेत्र में गौशाला के पास वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन किए जाने की सूचना मिलने पर वन विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम जांच के लिए गई थी। वन विभाग की टीम में सहायक वन संरक्षक कमलचन्द, हरेन्द्र भाकर, सहायक वनपाल पिंकू कुमार सहित अन्य कार्मिक शामिल थे। वहीं खनन विभाग की ओर से खनिज कार्यदेशक रमेशचन्द मय टीम मौके पर पहुंचे। संयुक्त टीम द्वारा रात्रि करीब 10 बजे मौके का निरीक्षण किया गया। आसपास के खनन पिट्स का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान करीब 10-12 व्यक्ति जिनमें नागरमल गुर्जर निवासी कालोटा, कालूराम गुर्जर निवासी कालोटा, प्रकाश गुर्जर निवासी सिलाटी की ढाणी हाल निवासी ननिहाल कालोटा, शैतान सिंह कालोटा, सुमेर निवासी सिलाटी की ढाणी हाल निवासी ननिहाल कालोटा व अन्य व्यक्ति थे, ने एकराय होकर राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए विभागीय टीम एवं राजकीय वाहनों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने खनन विभाग के राजकीय वाहन के शीशे तोड़ दिए तथा विभागीय कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिससे कुछ कार्मिकों को चोटें आई। स्थिति गंभीर होने पर खनन विभाग की टीम मौके से रवाना हुई, जिनका आरोपियों द्वारा ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो वाहन से पीछा भी किया गया।

घटना की सूचना तत्काल पुलिस उपाधीक्षक खेतड़ी एवं थाना बबाई को दी गई, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा विभागीय टीम को सुरक्षित थाना बबाई लाया गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आरोपियों की तलाश की तथा उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी नागरमल, कालूराम व जयचन्द उर्फ शौतानसिंह को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी राजपाल, एएसआई पप्पुराम, कांस्टेबल राजेश कुमार, सुगरसिंह आदि शामिल थे।

पांच हजार का इनामी 'मिन्डा' दिल्ली से गिरफ्तार

जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था आरोपी

चिड़ावा, (निसं)। पुलिस थाना चिड़ावा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए के इनामी एवं थाना स्तर के टॉप-टेन वांछित अपराधी सुनील सिंह उर्फ मिन्डा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था और दिल्ली में खानाबदोशों के बीच रहकर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था।

पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशानुसार वृत्ताधिकारी चिड़ावा विकास धींधवाल के सुपरविजन में थाना प्रभारी अम्बिका चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील सिंह उर्फ मिन्डा के खिलाफ माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। लगातार फरार रहने के कारण उसे थाना स्तर की टॉप-टेन वांछित अपराधियों की सूची में शामिल कर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम लगातार तलाश में जुटी हुई थी।

■ दिल्ली में खानाबदोशों के बीच रहकर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था आरोपी

इसी दौरान थाना चिड़ावा के आसूचना अधिकारी कांस्टेबल अमित सिहाग को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 मई को दिल्ली के द्वारका से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में आसूचना अधिकारी कांस्टेबल अमित सिहाग की विशेष भूमिका रही। टीम में उप निरीक्षक कैलाश चंद्र, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, कांस्टेबल अमित सिहाग एवं कांस्टेबल विकास शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपी सुनील सिंह उर्फ मिन्डा पुत्र विजयसिंह (40) निवासी छापड़ा, थाना पिलानी, जिला झुंझुनूं का है।

भीलवाड़ा में डकैती और तस्करी के इनामी बदमाश गिरफ्तार

■ फरारी के दौरान गांव-गांव जाकर सामान बेचने का काम कर रहा था ताकि पुलिस से बच सके

भीलवाड़ा, (निसं)। राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत भीलवाड़ा की बिजौलियां थाना पुलिस ने डकैती, एनडीपीएस और वर्षों से फरार चल रहे तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी ऐसे हैं, जिन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

थानाधिकारी स्वागत पाण्ड्या के नेतृत्व में गठित टीम ने डकैती के मामलों में 16 साल से फरार चल रहे 5 हजार के इनामी अपराधी राजू कालबेलिया निवासी बडोली, चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2010 से डकैती के दो मामलों में वांछित था। एनडीपीएस एक्ट के मामले में 13 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश मुकेश उर्फ संतोष बंजारा निवासी मंदसौर, मप्र. को भी पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी 2013 में 194 किलो अवैध डोडा-पोस्त तस्करी के दौरान पुलिस को चकमा देकर ड्राइवर सीट से कूदकर फरार हो गया था। फरारी के दौरान वह गांव-गांव जाकर सामान बेचने का काम कर रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। इस पर भी 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तीसरी कार्रवाई स्थाई वारंटी राधेश्याम उर्फ राधिया कंजर की गिरफ्तारी के रूप में मिली। आरोपी पिछले 12 साल से जंगलों में रहकर फरारी काट रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना पूरा हुलिया भी बदल लिया था, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने उसे चिताबड़ा क्षेत्र से धर दबोचा।

हनुमानगढ़ में बारिश के बाद मौसम में बदलाव दिखा

हनुमानगढ़, (निसं)। जिले में सुबह हुई हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण उमस बढ़ गई है। बारिश से मिली एक दिन की राहत के बाद अब गर्मी का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि होगी और सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह की बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली।

हालांकि, मंगलवार को मौसम पूरी तरह साफ हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर गर्म हवाएं चलेंगी। दिन और रात के तापमान में वृद्धि के साथ लू का प्रभाव भी देखा जा सकता है।

राजसमन्द में सड़क पर तीन पैंथर दिखे

राजसमन्द, (निसं)। केलवा क्षेत्र के आत्मा कुंवारिया-राती तलाई मार्ग पर देर रात एक साथ तीन पैंथर दिखाई देने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सड़क से गुजर रहे एक कार सवार युवक ने पैंथरों का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात आत्मा कुंवारिया रोड पर अचानक सड़क किनारे तीन पैंथर घूमते नजर आए। कुछ देर तक तीनों पैंथर सड़क के आसपास टहलते रहे, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों में भय व्याप्त हो गया। कार सवार लोगों ने सावधानी बरतते हुए अपने वाहन रोक लिए और दूर से ही वीडियो रिकॉर्ड किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के आस-पास पहाड़ी और जंगल इलाका होने के कारण कई बार जंगली जानवरों की आवाजाही देखी जाती रही है, लेकिन एक साथ तीन पैंथर दिखाई देना बेहद चौंकाने वाली घटना है। घटना के बाद रात के समय लोगों ने अकेले बाहर निकलने से परहेज किया। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने एवं पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।

अफीम के मामले में सरकारी अध्यापक को सजा सुनाई

जोधपुर, (कासं)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम और अफीम की खरीद फरोख्त की राशि के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरकारी अध्यापक को दो वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 1 जून 2014 को पुलिस थाना चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के तत्कालीन थानाधिकारी अमित सिहाग ने रमेश बेनीवाल से उसके मकान नंबर 77 बालाजी नगर, रूप रजत रोड, जोधपुर के घर में पलंग की प्लाई के नीचे छुपाकर रखी 100 ग्राम अवैध अफीम और अफीम के खरीद फरोख्त के 12.03 लाख रुपए बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी डारों की ढाणी, डोली कल्ला, कल्याणपुर के सरकारी विद्यालय में अध्यापक लगा हुआ था। उसने पूछताछ के दौरान अपने ताऊ के लड़के भागीरथ बेनीवाल निवासी गोदावास कल्याणपुर बालोतरा से 12 किलो अफीम खरीदकर आगे लोगों को अफीम बेचकर 12 लाख की राशि इकठ्ठा करना बताया। भागीरथ भी बागजी बाबल की ढाणी, डोली कल्ला, कल्याणपुर के सरकारी विद्यालय में अध्यापक लगा हुआ था। बाद अनुसंधान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की।

गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और अभियुक्तों के सरकारी विद्यालय में अध्यापक होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की, जबकि आरोपियों ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत 11 गवाह, 34 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त रमेशचंद्र बेनीवाल पुत्र बाबूलाल निवासी गांव गोदावास, कल्याणपुर, बालोतरा को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में 2 वर्ष की कठोर सजा व बीस हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई तथा सह अभियुक्त भागीरथ बेनीवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

अलवर : एनीकट का पानी रहस्यमयी तरीके से बदल रहा रंग

अलवर, (निसं)। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम चौमू में स्थित घाटा एनीकट इन दिनों चर्चा और डर का विषय बना हुआ है। स्थानीय निवासियों के लिए यह जोहड़ न केवल जल का स्त्रोत है, बल्कि वन्यजीवों और मवेशियों की प्यास बुझाने का मुख्य स्थान भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां का पानी किसी रहस्यमयी जहर में तब्दील होता दिख रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, इस जोहड़ के पानी में एक अजीबोगरीब बदलाव देखा जा रहा है। दिन के समय सूरज की रोशनी में पानी पूरी तरह से लाल नजर आता है, वहीं सूरज ढलते ही शाम होते-होते इसका रंग बदलकर हरा हो जाता है। पानी के इस तरह रंग बदलने और उसमें से आ रही दुर्गंध ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव के युवा राजाराम, प्रदीप, नवीन, मोनू और पंकज पक्षियों के लिए रखे परिंडों में पानी भरने एनीकट के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। पानी की सतह पर कई कछुए मृत अवस्था में तैर रहे थे। सिर्फ जलीय जीव ही नहीं, बल्कि प्यास बुझाने आया एक मोर भी वहां घायल हालत में मिला।

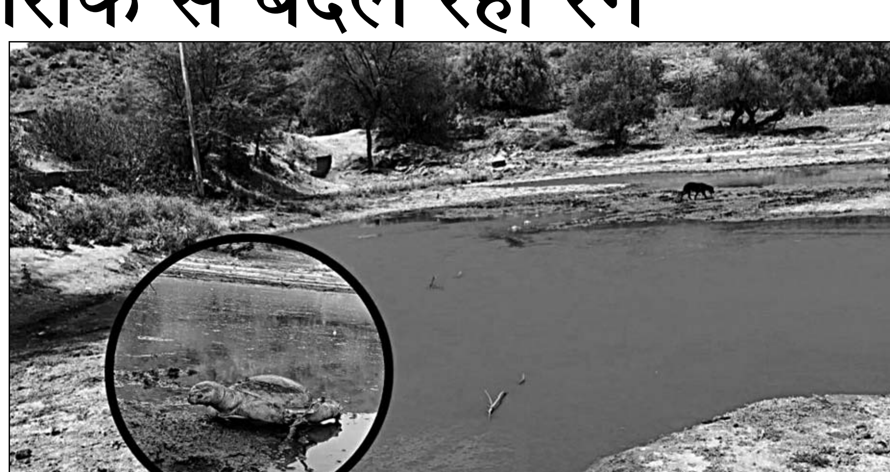

अलवर के ग्राम चौमू में स्थित घाटा एनीकट में कुछ दिनों से पानी रंग बलतला दिख रहा है।

अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिलेभर में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल वाहन और बजरी जब्त की, बल्कि अवैध रास्तों को भी जेसीबी से खुदवाकर बंद कर दिया है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों में कुल 26 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 ट्रैक्टर मय ट्रॉली, एक जेसीबी, एक लोडर और एक डंपर को अवैध बजरी के साथ जब्त किया है। परिवहन की जा रही 140 टन अवैध बजरी को भी कब्जे में लिया गया है।

थाना सदर क्षेत्र में विद्या कॉलेज के पास और ग्राम पोड्रास स्थित कोठारी नदी में रखे 700 टन अवैध बजरी स्टॉक को पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त रूप से नष्ट (खुर्द-बुर्द) किया। जहाजपुर में यहां पुलिस ने 160 टन बजरी का स्टॉक जब्त कर मामला दर्ज किया। बागोर व कारोई में संयुक्त टीम ने अमरगढ़ पिथास में दबिश देकर 50 टन बजरी जब्त की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में जाल बिछाया। सबसे अधिक 4 मामले माण्डलगढ़ थाने में दर्ज हुए।

एसीएस उच्च शिक्षा से मिले प्रो. बैरवा

जयपुर। राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर के नोडल अधिकारी एवं राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रो. रमेश बैरवा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस उच्च शिक्षा कुलदीप रांका से मुलाकात की। इनकी निजी पत्रावली को गुम करने वालों के खिलाफ कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिसके लिए एसीएस से इन्हें आश्वासन मिला है।

प्रो. बैरवा ने एसीएस को अपनी पीड़ा बताते हुए लिखा है कि इनकी सेवानिवृति 31.05.2026 को है। 03.05.2023 को इन्होंने राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कार्यग्रहण किया था। 19.10.2022 को हुए निलंबन के कारण इनके खिलाफ विभागीय जांच लम्बित है। विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने के लिए इन्हें सेवा प्रारंभ की तिथि 29.7.1995 से बनी 600 से अधिक पृष्ठों की इनकी नीजि पत्रावली से अनेक प्रमाणित दस्तावेजों की सख्त जरूरत है। इस हेतु इन्होंने प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से बार बार निवेदन किया है। गंगापुर सिटी प्राचार्य ने इन्हें अवगत कराया कि इनकी नीजि पत्रावली अभी तक राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी को प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए कई बार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं इनके पूर्व के पदस्थापन बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर को पत्र भेजे जा चुके हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा लिखता है कि प्रो. बैरवा की निजी पत्रावली इनके पूर्व के पदस्थापन बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से मंगा ली जाए जिसके लिए प्राचार्य गंगापुर सिटी ने अलवर कॉलेज प्राचार्य को पत्र भेजे। लेकिन जवाब प्राप्त हुआ कि तत्कालीन संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार प्रो रमेश बैरवा की निजी पत्रावली सेवा पुस्तिका के साथ 3.11.2022 को आयुक्तालय भेजी थी।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चार लाख रुपए के चोरी किए गए सोने के कंगन बरामद किए हैं। थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि 12 जनवरी को शीला निवासी वार्ड 19 ने रिपोर्ट दी कि 11 जनवरी को सुबह 8.30 पर घर के ताला लगाकर जयपुर गई थी। शाम के समय करीब 7 बजे घर पर वापस आई और मेन गेट का ताला खोलकर मकान में गई तब देखा दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैड मे रखे नकद रुपये व अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर लिये तथा कमरो में तोड़फोड़ कर डीवीआर भी चोरी कर ले गया। पुलिस ने तकनिकी की सहायता से काफी प्रयास के बावजूद आरोपी सोमवीर ऊर्फ मोटू पुत्र रोहिताश्व निवासी चेलापुरी खेतड़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ कर जेवरात व नकदी, मोबाईल फोन बरामद किया गया।

चूरू : रिश्तेदारों के नाम फर्जी जमीन दिखाकर नौ करोड़ का क्लेम उठाया

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया

चूरू, (कासं)। पुलिस ने रिश्तेदारों के नाम फर्जी जमीन दिखाकर 9 करोड़ रुपए क्लेम उठाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू निश्चय प्रसाद एम आईपीएस ने बतया कि 14 फरवरी को गोविन्दसिंह राठौड़ पुत्र नरोतम सिंह राजपूत निवासी चरला सुजानगढ़ सदर जिला चूरू हाल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सुजानगढ़ ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत सरकार की फसल बीमा योजना अन्तर्गत राज्य के किसानों की फसलों का स्वैच्छिक बीमा किया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना 19 जून 2025 को जारी हुई थी, अधिसूचना के अनुसार रबी की फसल में 15 प्रतिशत प्रीमियम किसान के द्वारा वहन किया जाता है एवं शेष प्रीमियम का भुगतान राजकोष से किया जाता है। जिसे राज्य एवं भारत सरकार के द्वारा आधा-आधा संयुक्त रुप से बैंक खाते के द्वारा वहन किया जाता है एवं संबंधित बीमा कंपनी को भेजी जाती है। इसी प्रकार से संबंधित बीमा क्लेम का भुगतान भी बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। मुझे जानकारी मिली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सालासर शाखा जिला चूरू के शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत, बैंक के कर्मचारी भागीरथ नायक जो कि फसल बीमा पोलिसी को जारी करता है एवं कुछ अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आपराधिक षडयन्त्र रचकर फर्जी बीमा किया जा रहा है, एवं राजकोष से प्रीमियम राशि का दुरुपयोग करते हुए फर्जी क्लेम उठाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में 71 विभिन्न नामों से पटवार मण्डल बज्जू तेजपुरा व ग्राम बज्जू खालसा के गांवों का सालासर ब्रांच के के.सी.सी. धारकों की फर्जी कृषि भूमि दिखाकर 13 लाख 51 हजार रुपये किसानों का प्रीमियम जमा करवा दिया।

इस प्रकार से फर्जी किसानों का प्रीमियम काट कर इसकी कुल क्लेम राशि करीब 9 करोड़ रुपए बनती है। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर सुभाष विश्नोई पुनि थानाधिकरी पुलिस थाना सालासर द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने मुल्जिम भागीरथ मल नायक पुत्र दानाराम निवासी बीदासर को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर पीसी रिमाण्ड हासिल किया गया।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 32.75 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

बैंक खाता किराए पर देने वाले दो स्थानीय युवक भी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा पुलिस ने पिछले 48 घंटों में सायबर अपराधियों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 32.75 लाख की ठगी करने वाले गुरुग्राम के एक शातिर हिस्ट्रीशीटर को दबोचा, बल्कि ठगों को अपना बैंक खाता किराए पर देने वाले दो स्थानीय युवकों को भी गिरफ्तार किया है।

मामले के अनुसार सायबर थाना पुलिस ने एक सेवानिवृत्त लेखाकार को सीबीआई अधिकारी बनकर डराने और उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने के मामले का खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के अनुसार, आरोपी अनिल कुमार उर्फ नन्हे (31) निवासी गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया है।

14 अप्रैल 2026 को प्रार्थी प्रहलाद राय सोडानी ने रिपोर्ट दी कि ठगों ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि उनके नाम से जारी सिम से अश्लील संदेश भेजे गए हैं। खुद को जज और पुलिस अधिकारी बताकर आरोपियों ने प्रार्थी और उनकी पत्नी को डराकर 32.75 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। सायबर टीम ने तकनीकी अनुसंधान के बाद गुरुग्राम में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी अनिल कुमार पर पहले से 15 मामले दर्ज हैं और वह हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खातों में 16.36 लाख रुपये होल्ड करवाए, जिसमें से 13.46 लाख रुपये प्रार्थी को वापस दिलाने के अदालती आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं।

दूसरी ओर, भीमगंज थाना पुलिस ने उन म्यूल अकाउंट धारकों पर शिकंजा कसा है जो लालच में आकर अपना बैंक खाता सायबर ठगों को बेच देते हैं। थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने बाबूलाल खटीक (30) और आशीष खोईवाल (22) निवासी पंचमुखी कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बाबूलाल के खाते से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान में सायबर ठगी की 6 गंभीर शिकायतें दर्ज थी। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने चंद रुपयों के लालच में अपनी बैंक डायरी, एटीएम और सिम कार्ड सायबर अपराधियों को सौंप दिए थे। इन खातों के जरिए लाखों का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है।

मैं बात को घुमाना नहीं चाहता। हमारी फील्डिंग और गेंदबाजी ने हमें मैच हराया। इस विकेट पर 210 रन 30 रन ज्यादा थे, क्योंकि गेंद सीम हो रही थी और बाउंस भी अनियमित था।

- श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स के कप्तान, अपनी टीम की हार को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी ▶ अक्षर पटेल

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग का यह मुकाबला 11 मई 2026 को धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें दिल्ली ने रोमांचक अंदाज में 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत न्यूनतम ओवर गति से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। चूंकि यह दिल्ली कैपिटल्स का इस सीजन पहला ओवर-रेट अपराध था।

क्या आप जानते हैं ?... सुनील छेत्री ने 115 मैच खेले हैं, जबकि भाईचुंग भूटिया ने 107 मैच खेले हैं। सुनील छेत्री ने 90 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं, जो सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे ज्यादा हैं।

गुजरात ने हैदराबाद को 82 रनों से हराया, अंकतालिका में बनी नं. 1

सुदर्शन-सुंदर के अर्धशतक, रबाडा और होल्डर को तीन-तीन विकेट

अहमदाबाद, 12 मई। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक जड़े। 169 रनों के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 100 रन भी नहीं बना पाई। वह 14.5 ओवर में 86 रन पर आउट हो गई। गुजरात टाइटंस ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। 16 अंक के साथ वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने 44 गेंद पर 61 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 33 गेंद पर 55 रन बनाए। निशांत सिंधु ने 22 रन बनाए। जेसन होल्डर 11 और राहुल तेवतिया 4 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल 5 और जोस बटलर 7 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रफुल हिंगे और साकिब हुैसन ने 2-2 विकेट लिए। पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा पैट कमिंस ने 19 रन बनाए। सलिल अरोड़ा ने 16, हेनरिक क्लासेन ने 16 और इशान किशन ने 11 रन बनाए। स्मरण रविचंद्रन ने 9, अभिषेक शर्मा ने 6, शिवांग कुमार ने 4 और प्रफुल हिंगे ने 3 और ट्रेविस हेड खाता नहीं खोल पाए। ईशान मलिंगा बगैर खाता खोले नाबाद रहे। गुजरात टाइटंस के लिए कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने 1-1 विकेट लिए। सनराइजर्स हैदरबाद की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है। गुजरात टाइटस की प्लेइंग 11 में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

थाईलैंड ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंची सात्विक-चिराग की जोड़ी

नई दिल्ली, 12 मई। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2026 के पुरुष युगल वर्ग में शानदार शुरुआत करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को खेले गए पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया के मुह पुत्रा एरवियांस्याह और बागस मौलाना की जोड़ी को कड़े संघर्ष में 21-19, 21-23, 21-10 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे और चार मिनट तक चला। पहला गेम बेहद रोमांचक रहा, जिसमें सात्विक और चिराग ने 21-19 से जीत दर्ज की। दूसरे गेम में इंडोनेशियाई जोड़ी ने वापसी करते हुए 23-21 से मुकाबला अपने नाम किया। हालांकि निर्णायक गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 21-10 से एकतरफा जीत हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। अब प्री-क्वार्टर फाइनल में सात्विक-चिराग की भिड़ंत मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गूंटिंग और मुहम्मद हैकाल की जोड़ी से होगी।

धर्मशाला पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम

धर्मशाला, 12 मई । एचपीसीए के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 14 मई को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बीच होने वाले मुकाबले के लिए मेहमान टीम मंगलवार को मैक्लोडगंज धर्मकोट के हयात रिजेंसी होटल पहुंच गई।

जयपुर ब्लूज क्लब ने मैत्री क्लब को हराया

जयपुर, 12 मई। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिवीजन लीग में आज खेले गए पूल बी के मैच में जयपुर ब्लूज क्लब ने मैत्री क्लब को 47 रनो से हराया। जी आर ग्राउंड पर जयपुर ब्लूज क्लब ने टॉस जीतकर पहले आलोक गुर्जर के 25 रन, लखन भारती के 18 रन, राहुल चौधरी के 31 रन, यथार्थ भारद्वाज के 81 रन, आर्यन सैनी के 26 रन व योगेंद्र काकोड़िया के 14 रन से 41.1 ओवर में 210 रन बनाकर आउट हो गई। मैत्री क्लब के लिए नीतिराज सिंह ने 32 पर 3, अमन खिलजी ने 27 पर 2, अनस मंसूरी ने 42 पर 2, हसन खान, आयुष अमेरियां व मनीष ने एक-एक विकेट लिया। जवाबी पारी में मैत्री क्लब की टीम रामदीप भार्गव के 28 रन, आयुष आमेरिया के 22 रन, अमन खिलजी के 37 रन, मनीष के 12 रन से 40.4 ओवर में 163 रन बनाकर आउट हो गई। जयपुर ब्लूज क्लब के लिए देव ऋषि रिजवानिया ने 24 पर 4, प्रतीक चौधरी ने 26 पर 3, राहुल चौधरी व योगेंद्र ने एक - एक विकेट लिया।

एसएमआर अकादमी जीती

जयपुर, 12 मई। अंडर-16 समर कप में एसएमआरक्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 210 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं। कृष चौधरी ने 65, वीर ने 36 और आरुष चौधरी ने 22 रन का योगदान दिया। आर्यन स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी की ओर से विहान अग्रवाल और गौरव प्रजापत ने 2-2 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आर्यन स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी 34 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। मयंक शर्मा ने सर्वाधिक 42 रनों का योगदान दिया। एसएम आरक्रिकेट अकादमी की ओर से आयुष शर्मा ने 3, तेजस जोशी और आरुष चौधरी ने 2-2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच कृष चौधरी को चुना गया।

आरडी एकेडमी ने अनंतम एकेडमी को हराया

जयपुर, 12 मई। राजस्थान यूथ क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय यूथ कप अंडर 17 में आज खेले गए मैच में आर डी एकेडमी ने अनंतम एकेडमी को 56 रनो से हराया। अनंतम ग्राउंड पर आर डी एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुद्र प्रताप सिंह के 27 रन, अमन तिरुपानी के 27 रन, मोहित शर्मा के 23 रन व जितेन गौतम के 14 रनो से 36.1 ओवर में 157 रन बनाए।अनंतम एकेडमी के लिए गर्व शर्मा ने 25 पर 2, हर्ष परवानी ने 20 पर 2, जवाबी पारी मे अरनिम भारद्वाज, अंश शर्मा, चिरायु व कर्णव कोठारी ने एक - एक विकेट लिया। जवाबी पारी में अनंतम एकेडमी की टीमहर्ष परवानी के 34 रन, गौरव शांतिवाल के 42 रन से25.5 ओवर में 101 रनो पर सिमट गई। आर डी एकेडमी के लिए अमन तिरुपानी ने 19 पर 6, हिमांक सैनी ने 28 पर 3 व लव्या गुप्ता ने 24 पर एक विकेट लिया।

आईपीएल 2026 : मैं खुद को 100 प्रतिशत गेंदबाज और 100 प्रतिशत बल्लेबाज मानता हूं : माधव तिवारी

धर्मशाला, 12 मई । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)2026 में सोमवार को धर्मशाला में खेले गए हाईस्कोरिंग मुकाबले में युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच लिया। आईपीएल 2026 में अपना पहला पूरा मुकाबला खेल रहे 22 वर्षीय माधव ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार योगदान देकर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ 3 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए। टीम की ओर से प्रियांश आर्य ने 33 गेंदों पर 56 रनों की विस्फोटक पारी खेली। हालांकि दिल्ली के युवा गेंदबाज माधव तिवारी ने उन्हें आउट कर पंजाब को बड़ा झटका दिया। माधव ने अपने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने कूपर कोनोली को भी धीमी बाउंसर पर पवेलियन भेजा। मैच के बाद माधव तिवारी ने कहा, सबसे पहले मैं टीम मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर चीजें आपके हाथ में नहीं होतीं तो आपको हर प्रैक्टिस सेशन में खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। मैंने गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल सर के साथ अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया।

डब्ल्यूएफआई से विवाद के बीच विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी साक्षी मलिक

नई दिल्ली, 12 मई । भारतीय ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने मंगलवार को साथी पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में आकर भारतीय कुश्ती महासंघ और सरकार से आग्रह किया कि तीन बार की ओलंपियन को गोंडा में सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 के ट्रायल में भाग लेने और अपनी वापसी की कोशिश जारी रखने की अनुमति दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में साक्षी ने कहा कि नियम ऐसे होने चाहिए जो महिला खिलाड़ियों को मातृत्व के बाद प्रतिस्पर्धी खेलों में वापसी के लिए प्रोत्साहित करें, न कि उनके खिलाफ बाधाएं खड़ी करें।

साक्षी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया विनेश के ट्रायल्स पर मेरी राय जानना चाहता है। मैं पिछले दो-तीन दिनों से इस बारे में सोच रही हूं क्योंकि विनेश एक पार्टी की सदस्य हैं और मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकती हूं जहां अन्य देशों के खेल संघ अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान बनाते हैं ताकि मां बनने के बाद भी महिलाएं देश के लिए खेल सकें और पदक जीत सकें।

आरसीए ने पूर्व कन्वीनर को 24 लाख जमा कराने का नोटिस भेजा था

नोटिस पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण एवं मेरी छवि खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास : कुमावत

जयपुर, 12 मई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीन दयाल कुमावत को 24 लाख रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आरसीए की ओर से 11 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें कुमावत पर संस्था के फंड के कथित अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है।

एडहॉक कमेटी ने दावा किया है कि आरसीए के खातों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि दीन दयाल कुमावत ने कन्वीनर पद पर रहते हुए 24 लाख रुपये विभिन्न अधिवक्ताओं को कानूनी शुल्क के रूप में भुगतान किए. यह भुगतान सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) से जुड़े कानूनी मामलों में किया गया था।

आरसीए की एडहॉक कमेटी का कहना है कि किसी जिला क्रिकेट संघ से संबंधित विवाद या मुकदमेबाजी का खर्च वहन करना आरसीए की जिम्मेदारी नहीं है। समिति ने इन भुगतानों को अनधिकृत मानते हुए पूरी राशि कुमावत से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का निर्णय लिया है। नोटिस में कहा गया है कि यह राशि आरसीए के खातों में उनके नाम पर डेबिट की जाएगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुमावत का यह कदम प्रथम दृष्टया उनके पद के दुरुपयोग और आरसीए के धन के ऐसे उपयोग को दर्शाता है, जो संस्था के उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित नहीं है।

एडहॉक कमेटी ने दीन दयाल कुमावत को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर 24 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर आरसीए उनके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। इसके अलावा डीसीए सवाई माधोपुर के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आरसीए ने स्पष्ट किया कि संस्था के फंड का उपयोग केवल क्रिकेट गतिविधियों के संचालन, प्रशासन और खेल के विकास के लिए किया जाना चाहिए।

वहीं, मामले को लेकर डीडी कुमावत का कहना है कि मेरे विरुद्ध राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया 24 लाख रुपये की रिकवरी का नोटिस पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण एवं मेरी छवि खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास है। मेरे 9 माह के कार्यकाल के दौरान मैंने आरसीए के हित में पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया।

जिन कानूनी भुगतानों को आज मुद्दा बनाया जा रहा है, वे सभी भुगतान आरसीए एवं कन्वीनर के पद से जुड़े मामलों में किए गए थे. ये कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं थे. यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेरे 9 माह के कार्यकाल के दौरान अनेक अवैध समिति बैठकों में मेरी अनुपस्थिति में कई अवैध निर्णय लिए गए, जिनमें समिति के कई सदस्य शामिल थे, लेकिन उस समय किसी ने भी मेरे विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं उठाया। यदि उस समय सब कुछ समिति की जानकारी एवं सहमति से चल रहा था, तो आज केवल मुझे निशाना बनाना पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है।

भुगतानों की जानकारी सदस्यों को थी : कुमावत का कहना है कि सभी बैंक भुगतान अधिकृत प्रक्रिया के तहत किए गए थे। बैंकिंग लेन-देन में आशीष तिवारी एवं पिंकेश जैन पोरवाल हस्ताक्षर प्राधिकारी थे दो चेक आशीष तिवारी द्वारा तथा तीन चेक पिंकेश जैन पोरवाल द्वारा हस्ताक्षिरत किए गए थे। इतना ही नहीं, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों एवं भुगतानों की जानकारी मौखिक रूप से समिति के सभी प्रमुख सदस्यों, जिनमें मोहित यादव एवं धनंजय सिंह को लगातार दी जाती रही थी।

यदि आरसीए को आज यह भुगतान अवैध प्रतीत होते हैं, तो उस समय के हस्ताक्षर प्राधिकारी पिंकेश जैन पोरवाल एवं आशीष तिवारी को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। साथ ही धनंजय सिंह एवं मोहित यादव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सभी भुगतानों एवं निर्णयों की जानकारी लगातार मौखिक रूप से दी जाती रही थी।

कुमावत ने यह भी कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान धनंजय सिंह, अरिशिष्ट सिंघवी एवं संपूर्ण जोधपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर कार्रवाई एवं निलंबन किया गया था। आज वही लोग और उनके समर्थक बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, तथा वर्तमान समिति पर दबाव बनाकर मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं।

यहां यह तथ्य भी जानकारी में आना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय में एक अनाधिकृत लोगों द्वारा याचिका रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जयपुर के विरुद्ध लगाई गई थी, जिसमें मुख्य पक्ष आरसीए एडहॉक कमेटी को बनाया गया था। डीसीए सवाई माधोपुर तो मुख्य याचिका में पक्षकार ही नहीं तो किया गया भुगतान डीसीए सवाई माधोपुर का कैसे माना जा सकता है? यदि मेरे विरुद्ध इस प्रकार के झूठे एवं मानहानिकारक आरोप लगाए जाते रहे, तो मैं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर एवं मानहानि की कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा।

कुमावत ने कहा कि मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने पूरे कार्यकाल में मैंने आरसीए से व्यक्तिगत उपयोग हेतु एक भी रुपया नहीं लिया और न ही कोई टीए-डीए लिया, जबकि मैं कानूनी रूप से उसका अधिकारी था। यह पूरा मामला मुझे दबाव में लेने, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने एवं जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। मैं इस प्रकार की राजनीति और चरित्र हनन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूँगा।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक :- न.नि.भ. / विधुत / 2026-27 / 172 दिनांक :- 06.05.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर निगम, भरतपुर द्वारा विद्युत सम्बन्धित 2 कार्य कराये जाने हेतु सम्बंधी कार्य हेतु EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.05.2026 से दिनांक 20.05.2026 समय 6:00 पी.एम. बजे निविदा तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते एवं विवरण वेसाईट (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) पर देखे जा सकते हैं।

UBN No. 1. DLB2627WSOB04192 2. DLB2627WSOB04192

अधिशाषी अभियंता (विधुत) नगर निगम, भरतपुर

राज.संवाद / सी / 26 / 2540

कार्यालय अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, कोटा

पता:- प्रथम तल जिला परिषद् भवन सीएडी कोटा, पिन कोड 324009

ई-मेल-SEWDSC.KOTA@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः लेखा / 2026-27/376 दिनांक : - 08/05/26

NOTICE INVITING BID

NIB No 04 YEAR 2026-27

Bids for NRM Works, estimated value INR 103.12 Lacs are invited from interested bidders up to 6.00 PM, 21.05.2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state.

NIB NO.-WSC2627A0198 UBN NO.-WSC2627WSOB00323

(उमेश चन्द्र गुप्ता) अधीक्षण अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कोटा

DIPR/C/8217/2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D. DISTT.DN.II, UDAIPUR

No.: 205 Date: 08.05.2026

Notice Inviting Bid No. 03/2026-27

NIB No.: PWD2627A0397

Bids for Atal Pragati Path 2026-27 work are invited from interested bidders upto 14.05.2026 11.00 AM to 25.05.2026 03.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal ("http://eproc.rajasthan.gov.in" and "http://sppp.rajasthan.gov.in") of the state, and department website. The approximate value of procurement of 1 No. is Rs. 145.00 Lacs.

1 UBN No.: PWD2627WSOB01873

(Anil Khichi) Executive Engineer, PWD Distt.Dn.II, Udaipur

DIPR/C/8248/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : 154 दिनांकः 08-05-26

ई-निविदा सूचना संख्याः 03/2026-27 खण्ड-द्वितीय सवाई माधोपुर

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड कार्यालय के अधीन उपखण्डो में खण्ड कार्यालय के अधीन उपखण्डो में वार्षिक अनुबंध के आधार पर वीवीआईपी मूवमेंट कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के यथोचित श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. 1. PWD2627WSOB01865, 2. PWD2627WSOB01866, 3. PWD2627WSOB01867

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड-द्वितीय सवाई माधोपुर

DIPR/C/8243/2026

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य, अजमेर

मृदंग सिनेमा के सामने, श्रीनगर रोड डिस्पेन्सरी के पास, पाल बीचला, अजमेर

दूरभाष नं. : 0145-2424944, ई-मेलः eemhajmer@ymail.com

क्रमांकः ई0 ई0 / अजमेर/26-27/230 दिनांकः 07/05/2026

निविदा सूचना संख्याः 05/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर सें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राशि 221.21 लाख के छः (6) कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट विवरण www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. NRH2627WSOB00183, 2. NRH2627WSOB00184, 3. NRH2627WSOB00185, 4. NRH2627WSOB00186, 5. NRH2627WSOB00187, 6. NRH2627WSOB00188

अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर

DIPR/C/8232/2026

कार्यालय नगर पालिका सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.)

E-mail id – npsultanpur01@gmail.com Ph.No. 07455-294166

क्रमांकः-नपासु0 / विकास / 2025-26 / 365-66 दिनांक:07.05.2026

ई-निविदा सूचना.../2025-26

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 88 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा कुल 1 कार्य की अनुमानित लागत 45.47 लाख की जाती है । नगर पालिका सुल्तानपुर की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु नियमानुसार डीएलबी में सक्षम श्रेणी एवं अन्य विभागों में A, AA श्रेणी में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से पंजीकृत संवेदकों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के सक्षम हो से ही ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

Work No.	UBN No.
1	DLB2627WSOB04204

प्रशासक नगर पालिका सुल्तानपुर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर

राज.संवाद / सी / 26 / 2551

कार्यालय नगर परिषद्, सरदारशहर (जिला चुरू)

Ph. 01564-220681, 220030 Email: eonpsdr@gmail.com

क्रमांक :- न.प.स. / 2026-27 / 2627-28 दिनांक :- 08.05.2026

निविदा सूचना सं. 08, 09 वर्ष 2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से नगर परिषद् सरदारशहर द्वारा 04 कार्यो के लिए ई-निविदा सूचना संख्या 08 वर्ष 2026-27 व 01 कार्य के लिए निविदा सूचना संख्या 09 वर्ष 2026-27 आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in पर तथा कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद् सरदारशहर के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकता है।

S.No.	निविदा संख्या	NIB CODE	UBN CODE
01	ई-निविदा सूचना सं. 08 वर्ष 2026-27	DLB2627A1555	DLB2627WSOB04158 DLB2627WSOB04159 DLB2627WSOB04160 DLB2627WSOB04161
02	निविदा सूचना सं. 09 वर्ष 2026-27	DLB2627A1557	DLB2627WSOB04164

आयुक्त नगर परिषद् सरदारशहर

राज.संवाद / सी / 26 / 2622

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा जिला कोटपूतली-बहरोड

क्रमांक : न.पा.पा.प्रा. / निर्माण / 2026-27 / 131 दिनांक : 07.05.2026

ई-निविदा सूचना संख्या (20/2026-27)

(NIB NUMBER- DLB2627A1469)

एतद्द्वारा यह है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।

निविदा के कुल कार्य – 30

यूबीएन नम्बर 1 से 30

DLB2627WSRC03996	DLB2627WSRC04018	DLB2627WSRC04022
DLB2627WSRC04025	DLB2627WSRC04028	DLB2627WSRC04032
DLB2627WSRC04035	DLB2627WSRC04036	DLB2627WSRC04040
DLB2627WSRC04042	DLB2627WSRC04045	DLB2627WSRC04046
DLB2627WSRC04050	DLB2627WSRC04053	DLB2627WSRC04054
DLB2627WSRC04056	DLB2627WSRC04057	DLB2627WSRC04059
DLB2627WSRC04060	DLB2627WSRC04061	DLB2627WSRC04064
DLB2627WSRC04067	DLB2627WSRC04068	DLB2627WSRC04069
DLB2627WSRC04071	DLB2627WSRC04072	DLB2627WSRC04073
DLB2627WSRC04074	DLB2627WSRC04075	DLB2627WSRC04076

राज.संवाद / सी / 26 / 2568 अधिशाषी अधिकारी

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक : प.5(21)एचजेयू / जीएडी / निविदा / 381 दिनांक : 12.05.2026

बोली आमंत्रण सूचना

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, दहमीकलां, बगरू, जयपुर की ओर से, पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्था / एजेन्सी / संवेदक से विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कार्यो हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है :

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	NIB एवं UBN No.	अनुमानित लागत (राशि रू.)	डाउनलोड प्रारंभ तिथि
1	मशीन विद्मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर- उच्च कुशल) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अकुशल) कार्य हेतु	NIB No. : HJU2627A0003 UBN No. : HJU2627SLOB00003	21.50 लाख	11.05.2026
2	सफाई कार्य हेतु	NIB No. : HJU2627A0002 UBN No. : HJU2627SLOB00002	15.00 लाख	11.05.2026
3	बागवानी कार्य हेतु	NIB No. : HJU2627A0004 UBN No. : HJU2627SSOB00004	6.10 लाख	12.05.2026

उपरोक्त क्र.संख्या 01 व 02, में ई-निविदाएं एवं क्रम संख्या 03 में निर्धारित प्रपत्र में मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण / शर्ते वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट https://www.hju.ac.in अथवा कार्यालय समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है।

राज.संवाद / सी / 26 / 2626 कुलसचिव

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज0)

फोन न.07464-294024, ई-मेल आईडी np.karauli@yahoo.com, website – WWW.npkarauli.in

क्रमांक : 845 दिनांक : 05.05.2026

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण एवं उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि नगरपरिषद करौली परिषद क्षेत्र निम्न कार्य कराना चाहती है। जिस हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विवरण व शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in & www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

कार्य का नाम	नगर परिषद क्षेत्र करौली में सीवर लाईन सफाई का कार्य (वार्षिक अनुबंध)
निविदा की अनुमानित लागत	17.97 लाख
धरोहर राशि	प्रत्येक कार्य हेतु अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत
ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने / डाउनलोड की तारीख	08.05.2026 समय 5:00 पीएम से 23.05.2026 समय 6:00 पीएम तक
ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम तिथि	23.05.2026 समय 6:00 पीएम तक
भौतिक रूप से निविदा शुल्क व दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि	25.05.2026 समय 2:00 पीएम तक
ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्राप्त निविदा खोलने की तिथि	26.05.2026 समय 3:30 पीएम
निविदा शुल्क	प्रत्येक कार्य हेतु 1000 / – रूपयें
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	प्रत्येक कार्य हेतु 500 / –रूपये
निविदा प्रपत्र व शर्ते डाउनलोडिंग बेबसाईट	eproc.rajasthan.gov.in
UBN. -	DLB2627SLRC04162

आयुक्त नगरपरिषद, करौली

राज.संवाद / सी / 26 / 2619

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचनाः-

क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/91

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4 (1) वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानुसार मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती हैः-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	15.05.2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रकियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Eamest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष कमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

DIPR/C/____/2026 आबकारी आयुक्त, राजस्थान

मुख्यमंत्री भजनलाल ने माँ कामाख्या देवी मंदिर में हवन किया

वे असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा के शपथ-ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए

गुवाहाटी/जयपुर, 12 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए। उन्होंने हवन में आहुति दी तथा पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की।

मुख्यमंत्री ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की और बच्चों को दुलार भी किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मंदिर आए प्रवासी राजस्थानियों में उत्साह नजर आया। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर का प्रतीकात्मक मॉडल भेंट कर मुख्यमंत्री रा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

- गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के समय उनकी पत्नी भी साथ थी। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत व अभिनंदन किया गया तथा मंदिर का प्रतिकात्मक मॉडल उन्हें भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में उन्होंने डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री एवं अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार असम में सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी तथा विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए।

अन्नाद्रमुक के बागी नेता मुख्यमंत्री विजय से मिले

चेन्नई, 12 मई। तमिलनाडु में बहुमत के जादुई आंकड़े को लेकर मची सियासी खींचतान के खेल में अब एक और अध्याय जुड़ गया है। विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण से पहले मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को बागी एआईएडीएमके नेताओं एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम से मुलाकात की। यह मुलाकात इस वजह से भी खास मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले ये नेता कल यानी बुधवार को विधानसभा में टीवीके को समर्थन दे सकते हैं। टीवीके प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले से ही कई सियासी दलों से समर्थन पा लिया था। हालांकि, इसके बावजूद सरकार में अनिश्चितता का माहौल है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण न होने तक ऐसा सियासी माहौल बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच एआईएडीएमके नेता षणमुगम और वेलुमणि ने विजय का समर्थन करने की खुलकर वकालत की। आशंका गहरा गई है कि लगभग 30 विधायकों का ये गुट एआईएडीएमके में टूट की वजह बन सकता है।

- यह माना जा रहा है करीब 30 बागी विधायक बुधवार को विधानसभा में टीवीके को समर्थन देंगे

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर फोकस हो तभी, विदेशी मुद्रा अर्जित हो पाएगी

फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स इन इंडिया टूरिज़्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी ने प्र.मंत्री मोदी की अनावश्यक विदेश यात्रा नहीं करने की अपील का समर्थन करते हुए सुझाव दिया

- फैडरेशन के महासचिव राजीव मेहरा ने बताया, गत दशक में भारतीयों की विदेश यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, इसमें भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पर विदेश यात्रा कम करने से थोड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत लाने पर फोकस करने वाली नीति बनानी चाहिए।
- राजीव मेहरा ने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावना है, पर भारत हर साल 2 करोड़ विदेशी पर्यटक ही खींच पाता है, जबकि कई छोटे देशों में इससे कई गुना ज्यादा पर्यटक जाते हैं।
- मेहरा ने कहा कि भारत को पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करना होगा, तभी वह इस क्षेत्र में टिक सकेगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच नागरिकों से गैर-आवश्यक विदेश यात्रा को एक वर्ष के लिए स्थगित करने का आग्रह करने के एक दिन बाद, फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स इन इंडिया टूरिज़्म एण्ड हॉस्पीटैलिटी (एफएआईटीएच) ने इस अपील का समर्थन किया, लेकिन साथ ही जोर दिया कि भारत को विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

फैडरेशन के महासचिव राजीव मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान वर्तमान वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच, जिसने ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा की है और ऊर्जा जरुरत के लिए आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाया है।

मेहरा ने कहा, "प्रधानमंत्री का बयान देश की चुनौतीपूर्ण विदेशी मुद्रा स्थिति पर चिंता को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। ऐसे हालात में, जहाँ संभव हो, कीमती विदेशी मुद्रा की बचत करना महत्वपूर्ण हो जाता है।"

उन्होंने प्रधानमंत्री के आ ान के व्यापक भाव का समर्थन करते हुए नागरिकों से विदेशी खर्च को कम करने का आग्रह किया, जिसमें छुट्टियों में विदेश यात्रा और विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स शामिल हैं।

पिछले दशक में, भारत से बाहरी पर्यटन में तेज वृद्धि हुई है, जिसमें लाखों भारतीय हर साल छुट्टी मनाने खरीददारी, शिक्षा और मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करते हैं। इसके साथ ही, थाईलैंड, यूएई, तुर्की, इटली और बाली जैसे देशों में डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी अधिक लोकप्रिय हो गई हैं, जिनमें भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

मेहरा ने कहा कि हालांकि बाहरी पर्यटन कम करने से थोड़े समय के लिए विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, लेकिन भारत को समानांतर रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों से विदेशी मुद्रा राजस्व को पर्याप्त रूप से बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो।

उन्होंने कहा, "विदेशी मुद्रा बचाना समीकरण का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि और अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भारत लाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करना।"

फैडरेशन के अनुसार, विशाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक विविधता के बावजूद, भारत वैश्विक पर्यटन में काफी कम प्रदर्शन कर रहा है। मेहरा ने कहा कि भारत हर साल केवल लगभग दो करोड़ विदेशी पर्यटक ही आकर्षित करता है, जो इसकी क्षमता से और कई छोटे देशों की तुलना में काफी कम है, जिन्होंने मजबूत पर्यटन अर्थव्यवस्थाएँ बनाई हैं।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश, जिसे विशाल प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिकता और विश्व-स्तरीय ऐतिहासिक स्मारकों का वरदान मिला है, इतनी सीमित संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि उचित नीति समर्थन और वैश्विक विपणन प्रयास किए जाएँ, तो भारत दुनिया के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में से एक बन सकता है।"

फैडरेशन ने एक व्यापक पर्यटन रणनीति की वकालत की, जिसमें आसान वीज़ा नियम, विस्तारित अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क, बेहतर पर्यटन बुनियादी ढांचा और मजबूत विदेशी प्रचार अभियान शामिल हैं।

उद्योग निकाय ने कहा कि जटिल वीज़ा प्रक्रियाएँ कई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निरुत्साहित करती हैं, खासकर जब प्रतिस्पर्धी गंतव्य देश आसान प्रवेश प्रणाली और आक्रामक पर्यटन विपणन प्रदान करते हैं। फैडरेशन ने प्रमुख पर्यटन मार्गों में अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी, शहरी स्वच्छता, सुरक्षा मानकों और आगंतुक सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मेहरा ने आगे कहा कि भारत का विदेशी पर्यटन प्रचार वैश्विक मानकों से काफी पीछे है और यदि देश प्रमुख पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो इसमें पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का मानना है कि आने वाले पर्यटक विदेशी मुद्रा आय, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्त्रोत बन सकते हैं, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितताएँ व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर रही हैं।

प्रधान मंत्री मोदी का यह आ ान भारत के आयात बिल पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, विशेष रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण, यह पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट से जुड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि गैर जरुरी कारणों से विदेशी मुद्रा बाहर जाने की प्रवृतियों को कम करना और साथ ही उन क्षेत्रों को मजबूत करना, जो विदेशी मुद्रा की आय उत्पन्न कर सकते हैं, भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकता है।

कूनो नैशनल पार्क में चार चीता शावकों की मौत

एक माह पूर्व इन चारों शावकों का जन्म हुआ था

श्योपुर, 12 मई। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक माह पहले जन्मे मादा चीता केजीपी-12 के चारों शावकों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह जब मॉनिटरिंग टीम श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन पहुंची, तब उन्हें डेन साइट के पास चारों शावकों के शव मिले। वन विभाग ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि की है।

विभाग ने जानकारी दी कि एक महीने पहले 11 अप्रैल 2026 को चारों शावकों का जन्म हुआ था। मॉनिटरिंग टीम ने 11 मई की शाम को इन्हें अंतिम बार जीवित देखा था। ये महज एक महीने के थे। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे गश्ती टीम जब नियमित मॉनिटरिंग के लिए पहुंची, तो मांद के पास चारों शावकों के शव मिले। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य जंगली जानवर ने इनका शिकार किया है, हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी।

- आशंका है कि किसी अन्य जंगली जानवर ने इनका शिकार किया है पर मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगी।

घटना के बाद गश्ती दल ने तुरंत वरिष्ठ वन अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची टीम ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पूरे कूनो क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और वन विभाग की टीम लगातार इलाके की जांच कर रही है। राहत की बात यह है कि मादा चीता केजीपी-12 पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ बताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। वन विभाग की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल मादा चीता सामान्य व्यवहार कर रही है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस घटना के बाद देश में कुल चीतों की संख्या घटकर 53 रह गई है। इनमें से 50 चीते कूनो नेशनल पार्क में और तीन चीते गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद हैं। इनमें से 33 चीते भारत में जन्मे हैं।

पीएम आवास के पास की तीन झुग्गी बस्ती हटा सकते हैं- हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 12 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक बसी तीन झुग्गी बस्तियों को हटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की बेंच इन झुग्गियों में रहने वालों को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते में जगह खाली कर दें।

कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास की ये झुग्गियां अनाधिकृत हैं। कोर्ट ने इन झुग्गियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सावदा घेवरा में पुनर्वासित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा कि पुनर्वास के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम बाधा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता एक वैध वजह है, जिसकी वजह से इन झुग्गियों को खाली कराया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि ये झुग्गियां सैन्य संस्थानों के बिल्कुल नजदीक हैं, जो काफी संवेदनशील इलाका है। केन्द्र सरकार ने वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसे स्थानों पर अनाधिकृत ढ ांचे खड़े नहीं किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। केन्द्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में बनी पुनर्वास कालोनियों में सात सौ से ज्यादा प्रभावितों को बसाया जा रहा है। इनमें से 192 ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से जारी आवंटन पत्र स्वीकार कर लिया है। 136 ने तो फ्लैट का कब्जा भी ले लिया है।

- अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इन झुग्गियों को खाली कराया जायेगा

दरअसल, उच्च न्यायालय में तीन झुग्गियों भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों ने याचिका दायर की थी। ये झुग्गियां दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के नजदीक हैं। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इन झुग्गियों के निवासियों को हटाने के लिए अक्टूबर 2025 और फरवरी 2026 में नोटिस जारी किया था।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन तथा 7 जून 2021 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार ही प्रभावी रहेंगी। अभ्यर्थियों को विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। आयोग ने बताया कि 16 मई से 30 मई 2026 तक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता अपडेट कर सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल दी है, तो वह 'फेच एप्लीकेशन फॉर्म' विकल्प के माध्यम से पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेगा। इससे पूर्व आवेदन से जुड़ी जानकारी नए सिस्टम में सुरक्षित रूप से जुड़ जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपडेट करना जरूरी होगा। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन में कोई संशोधन नहीं करना है, उन्हें भी एडिट मोड में जाकर लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग के लिए अनिवार्य सहमति देनी होगी। इसके बाद फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी किए बिना आवेदन सब्मिट नहीं माना जाएगा।

पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिये- होसबाले

नई दिल्ली, 12 मई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक चुभन जरूर है, लेकिन पड़ोसी देश (पाकिस्तान) के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। बता दें कि दत्तात्रेय होसबाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं।

आरएसएस महासचिव ने न्यूज एजेंसी से कहा कि अगर पाकिस्तान एक सुई की नोक की तरह पुलवामा जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता है, तो हमें हालात के हिसाब से सही जवाब देना होगा।

मु.मंत्री के नाम पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की पूरी जानकारी थी और उनसे कुछ भी छुपाया नहीं गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, एआईसीसी से वेणुगोपाल को हटाना चाहती है, लेकिन नेतृत्व को समग्र तस्वीर पर ध्यान देना होगा। पाँच राज्यों के चुनावों के बाद सभी सरकारें और मुख्यमंत्री अपने पदों पर हैं, सिवाय कांग्रेस केरल इकाई के, जो अभी अनिश्चित स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार, प्रयास किए जा रहे हैं कि सतीशन को शांत किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी वेणुगोपाल को केरल भेजना चाहते हैं, लेकिन वेणुगोपाल केवल मुख्यमंत्री बनने के वचन पर ही शांत होने को तैयार हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, निर्णय अब होगा, जल्दी या देर से। पार्टी यह संदेश नहीं भेजना चाहती कि वह अस्थिरता, निर्णयहीनता और अनिश्चितता की स्थिति में है।

पेपर लीक के कारण नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया गया। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि मई 2026 चक्र के लिए पंजीकरण डेटा, उम्मीदवार विवरण और परीक्षा केन्द्र वैध रहेंगे। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नीट (यूजी), जो भारत भर में , एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा है, 3 मई को भारत के 551 शहरों में 5,400 से अधिक केन्द्रों और विदेश के 14 शहरों में पे-एंड-पेपर मोड में आयोजित की गई थी। करीब 22.79 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था।

हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने

गुवाहाटी, 12 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की लगातार तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है। गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित भव्य समारोह में डॉ. सरमा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत, राजग शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ली।

आज हो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूडीएफ ने विधानसभा की 140 सीटों में से 102 पर शानदार जीत दर्ज की, और यह एक दशक के बाद ऐतिहासिक वापसी है।

'एक ज्योतिषी को ओएसडी का पद क्यों, क्या कोई बताएगा'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय द्वारा ज्योतिषी को अपना राजनैतिक ओएसडी नियुक्त करने पर कांग्रेस सांसद ने सवाल किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की छवि को खराब करने के लिए लगता है, एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के प्रमुख ज्योतिषी और तमिझागा वेत्रि कझगम (टीवीके) प्रवक्ता राधन पंडित वेत्रिवेल को नई सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी (राजनीतिक) के रूप में नियुक्त करने को लेकर अनावश्यक रुप से विवाद खड़ा किया जा रहा है।

पंडित, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, को टीवीके नेतृत्व का करीबी सहयोगी माना जाता है और वे पार्टी की आउटरीच गतिविधियों में सक्रिय रहे। मई 10 को विजय के शपथ ग्रहण समारोह को अपरान्ह 3:45 बजे से उसी दिन सुबह 10 बजे करने का निर्णय पंडित वेत्रिवेल की सलाह पर लिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, रिक्की राधन पंडित वेत्रिवेल को मुख्यमंत्री का ओएसडी (राजनीतिक) नियुक्त किया जाता है, यह आदेश नियुक्ति की तिथि से प्रभावी होगा। इस संबंध में शर्तें और नियम अलग से जारी किए जाएंगे। पंडित वेत्रिवेल विजय के निजी ज्योतिषी हैं और उन्होंने अभिनेता-राजनेता को उनके राजनीतिक सफर में निरंतर सलाह दी है। हालांकि, कांग्रेस में कुछ लोगों को यह नियुक्ति पसंद नहीं आई, जो विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के गठबंधन सहयोगी हैं।

- कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी मु.मंत्री विजय के इस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा, सरकार जवाबदेही और प्रोफेशनलिज़्म पर चलनी चाहिए अंधविश्वास पर नहीं।
- ज्योतिषी राधान पंडित टीवीके पार्टी के प्रवक्ता हैं और लंबे समय से विजय के सलाहकार हैं। बताया जाता है कि उन्हीं के कहने पर शपथ ग्रहण का समय शाम पौने चार से बदल कर सुबह दस बजे किया गया था।

थिरुवल्लुर के कांग्रेस सांसद ससीकांत सेनथिल ने पूछा: "मुझे समझ नहीं आता। एक ज्योतिषी को ओएसडी पद की आवश्यकता क्यों होगी? क्या कोई समझा सकता है?"

सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुम्भार ने भी नियुक्ति की आलोचना की और कहा कि तमिलनाडु को ऐसे प्रशासन की आवश्यकता है जो योग्यता, पेशेवराना क्षमता (प्रोफेशनलिज़्म) और जवाबदेही पर आधारित हो, न कि अंधविश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा पर।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में निजी ज्योतिषी को नियुक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में परेशान करने वाला संदेश देता है और संस्थागत विश्वसनीयता को कम करता है। सार्वजनिक पद अंधविश्वास या पक्षपात की जगह नहीं है।"

हालांकि, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इस नियुक्ति की रिपोर्टिंग करते समय इस तथ्य की उपेक्षा कर रहे हैं कि ज्योतिष और ज्योतिषियों की सलाह, कुछ के अलावा, लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा मांगी जाती रही है। पिछले पांच दशकों में राजनीतिक रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर, लेखक ने कहा कि बड़े और छोटे नेता ज्योतिषियों की सलाह लेते रहे हैं। यहां तक कि देश की स्वतंत्रता की घोषणा के लिये मध्यरात्रि समय भी उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सूर्यनारायण व्यास और पंडित हरिदेव शर्मा त्रिवेदी ने सुझाया था।

अनावश्यक विवाद खड़ा करना केवल यह दिखाता है कि देश में अधिकांश लोग दोहरी मानसिकता अपनाते हैं। वे निजी तौर पर जिन चीजों का समर्थन करते हैं, और उन्हें पसन्द करते हैं, उन्हीं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हैं।

इस बीच, विजय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज पूजा स्थलों, शैक्षिणक संस्थानों और बस स्टेशनों से 500 मीटर की दूरी के अन्दर संचालित 717 सरकारी टीएएसएमएसी शराब रिटेल आउटलेट्स को दो सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने इस कदम से पहले राज्यव्यापी सर्वेक्षण का आदेश दिया था, ताकि संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों के पास स्थित शराब की ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय जनहित और सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों द्वारा उठाई गई लंबित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

अमेरिका, पाकिस्तान की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कूटनीति के क्षेत्र में भी पूरी हो।"

ट्रम्प ने तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया और चेतावनी दी कि अस्थिर संघर्ष विराम अब "लाइफ सपोर्ट पर" है।

ट्रंप ने कहा, "वो जो कचरा हमें भेजा, उसे पढ़ने के बाद मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा। वे लाइफ सपोर्ट पर हैं। संघर्ष विराम बड़े पैमाने पर लाइफ सपोर्ट पर है।" उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान को सैन्य रूप से कमज़ोर किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि संघर्ष विराम के दौरान तेहरान द्वारा किये गये किसी भी सैन्य पुनर्निर्माण को "लगभग एक दिन में नष्ट किया जा सकता है।"

इस बीच, बढ़ती आलोचना के बीच, पाकिस्तान ने सी.बी.एस. की रिपोर्ट को जोरदार रूप से खारिज किया और इसे "भ्रामक और सनसनीखेज" बताया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान पूरी तरह से सी.बी.एस. न्यूज़ की रिपोर्ट को भ्रामक और सनसनीखेज मानता है, जिसमें नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों की उपस्थिति का उल्लेख है।"

इस्लामाबाद ने कहा कि संघर्ष विराम अवधि और वार्ता के पहले दौर के दौरान, कई ईरानी और अमेरिकी विमान केवल कूटनीतिक कर्मचारियों, सुरक्षा टीमों और प्रशासनिक कर्मचारियों की आवाजाही के समर्थन के लिए पाकिस्तान आए थे।

पाकिस्तान के अनुसार, रावलपिंडी में वर्तमान में खड़े ईरानी आर.सी.-130 विमान का संघर्ष विराम अवधि के दौरान आगमन हुआ और इसका किसी भी सैन्य आपात स्थिति या संरक्षण व्यवस्था से "कोई भी संबंध नहीं था।" पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, "इसके विपरीत दावे अनुमानित, भ्रामक और तथ्यात्मक संदर्भ से पूरी तरह अलग हैं।" मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान संवाद और तनाव कम करने के प्रयासों में "निष्पक्ष, रचनात्मक और जिम्मेदार मध्यस्थ" के रूप में कार्य कर रहा है।

फिर भी, इस विवाद ने वाशिंगटन में राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रम्प के करीबी सहयोगी हैं, ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की तटस्थता पर सवाल उठाया।

ग्राहम ने एक्स पर लिखा, "यदि यह रिपोर्टिंग सटीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान की ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में भूमिका का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होगा।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों द्वारा इज़रायल के प्रति पूर्व वक्तव्यों को देखते हुए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, अगर यह सच हो।"

अब, जबकि ट्रम्प चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बीजिंग जा रहे हैं तो यह अटकलें तेज हो गई हैं कि चीन पश्चिम एशिया को स्थिर करने के प्रयासों में अधिक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है, खासकर जब पाकिस्तान की, मध्यस्थ की भूमिका में विश्वास कमज़ोर होता दिख रहा है।

भारत ने रूस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपग्रह ट्रैकिंग से छुपाना बहुत कठिन है।

भारत अधिकृत रूसी एलएनजी खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी अधिकांश मात्रा यूरोप के लिए है। चीन भी रूस की प्रतिबंधित और गैर-प्रतिबंधित, दोनों प्रकार की एलएनजी का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। सूत्रों ने आगे कहा, मॉस्को भारत के साथ एलएनजी और उर्वरक, जैसे पोटाश, फास्फोरस और यूरिया आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते करने की कोशिश कर रहा है। ईरान संघर्ष के कारण होर्मुज़ स्ट्रेट मार्ग से शिपिंग बाधित होने से पहले, भारत अपनी गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता था, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत इसी जलमार्ग से आता था। इसके अलावा, अपनी क्रूड तेल की आधी से अधिक आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती थी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घर से काम करने, विदेशी यात्रा सीमित करने और सोने व खाद्य तेल के आयात को कम करने का आग्रह किया।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908